हरियाणा विधानसभा

की

कार्यवाही

27 मार्च, 1979

खंड 1, अंक 17

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 27 मार्च, 1979

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उतर	(17)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उतर	(17)24
पब्लिक अकाउंटस कमेटी की तेरहवीं रिपोर्ट पे करना	(17)27
वर्श 1979–80 के लिए बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनराम्भ)	(17)28

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 27 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

तांराकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्षः साहेबानए अब सवाल होंगे।

Freedom Fighters in the State

1189. Master Shiv Parshad: Will the Chief Minister be pleased state-

(a) the district-wise and tehsil-wise number of the freedom fighters in Haryana to whom the pension is being paid together with the amount thereof in each case; and

(b) whether it has come to the notice of the Government that pension is being given to some undeserving persons, if, so, the steps being taken or proposed to be taken by the Government in this respect?

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): (क) जो माली इमदाद फ्रीडम फाइटर्ज राज्य सरकार और भारत सरकार देती है उससे

संबंधित सूचना फहरिस्त नं0 1 से 4 में दी गई है जिसे हाउस के पटल पर रखा जाता है।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए है। ऐसे मामलों की रिपोर्ट भारत सरकार के नोटिस में लाई जाती है और रिकमैंडे ान भेजी जाती है और उस पर वह फैसला करती है।

ANNEXURE-1

District-wise list of General Freedom Fighters and the rates of financial assistance given by the State Government

Name of District	Rs. 25/- p.m.	Rs. 30/- p.m.	Rs. 50/- p.m.	Rs. 75/- p.m.	Rs. 100/- p.m.	Rs. 150/- p.m.	Rs. 200/- p.m.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ambala	19	6	5	2	2	-	-	34
Bhiwani	2	1	-	-	-	-	-	3
Gurgaon	4	-	1	-	-	-	1	6
Hissar	11	4	-	-	-	-	-	15
Jind	6	-	5	-	-	-	-	11
Karnal	25	13	4	1	3	1	-	47

Kurukshetra	10	5	-	-	-	-	-	15
Mohindergarh	4	-	1	-	1	-	1	7
Rohtak	49	5	4	-	1	-	-	59
Sonepat	24	3	2	-	-	1	-	30
Sirsa	8	-	-	-	-	-	-	8
Total	162	37	22	3	7	2	2	235

ANNEXURE-II

District-wise list of the Ex. I.N.A. Personnel and the rates of financial assistance give by the State Government

Name of District	Rs. 25/- p.m.	Rs. 30/- p.m.	Rs. 50/- p.m.	Rs. 75/- p.m.	Rs. 100/- p.m.	Rs. 150/- p.m.	Rs. 200/- p.m.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ambala	22	1	-	-	-	-	-	23
Bhiwani	130	10	-	-	-	-	-	140
Gurgaon	123	12	-	-	-	-	-	135
Hissar	151	10	5	-	-	-	-	166

Jind	37	4	1	-	-	-	-	42
Karnal	11	3	1	-	-	-	-	15
Kurukshetra	20	1	-	-	-	-	-	21
Mohindergarh	116	7	2	-	-	-	-	125
Rohtak	239	17	2	-	-	-	-	258
Sonepat	29	1	-	-	-	-	-	30
Sirsa	17	2	-	-	-	-	-	19
Total	859	68	11	-	-	-	-	974

ANNEXURE-III

District-wise list of the General Freedom Fighter who are getting pension under the Government of India Scheme, 1972 and the rate of pension

Name of District	Rs. 200/- p.m.	Rs. 175/- p.m.	Rs. 100/- p.m.	Total
Ambala	107	4	29	140
Bhiwani	36	1	6	43
Gurgaon	68	1	76	76
Hissar	150	3	35	188

Jind	12	1	3	16
Karnal	141	4	32	177
Kurukshetra	27	4	4	35
Mohindergarh	54	5	9	68
Rohtak	162	9	36	207
Sonepat	91	11	29	131
Sirsa	35	-	4	39
Total	883	43	194	1120

ANNEXURE-IV

District-wise list of Ex. I.N.A. Personnel who are getting pension under the Government of India Scheme 1972 and the rate of pension per month.

Name of District	Rs. 200/- p.m.	Rs. 175/- p.m.	Rs. 100/- p.m.	Total
Ambala	66	2	4	72
Bhiwani	245	19	36	300
Gurgaon	269	17	41	327
Hissar	275	20	25	320
Jind	64	2	8	74

Karnal	80	1	11	62
Kurukshetra	52	1	4	57
Mohindergarh	324	25	45	394
Rohtak	535	30	84	649
Sonepat	103	4	14	121
Sirsa	40	3	1	44
Total	2023	124	273	2420

मास्टर ि ाव प्रसादः मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात उनके नोटिस में है कि अम्बाला जिला में कुछ ऐसे केसिज है कि अन–डिजर्विंग होने के बावजूद भी लोग पैं ान ले रहे है?

चौधरी देवी लालः इस बात की जिलेवार सूचना तो मेरे पास नहीं है। यह सारी लिस्ट मेरे पास है जो मैं पढ़कर सुना देता हूं। यह लिस्ट मैं इसलिये भी पढ़कर सुनाना जरूरी समझता हूं क्योंकि आज हमारी बहुत ही खु ाकिस्मती है कि पहला ही सवाल फ्रीडम फाईटर्ज का है और जो फ्रीडम फाईटर्ज के अगवा थे जिनका नाम आपने सुना होगा, श्री जितेंद्र नाथ दास जिन्होंने 63 दिन तक भूख हड़ताल करके अपनी जिन्दगी कुर्बान की थी उनके भाई और बाल–बच्चे आज हमारे सामने यहां स्पै ाल गैलरी में बैठे है। राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और साबका आई0एन0ए0 के सैनिकों को प्रति वर्श के आधार पर

माली इमदाद देती है न कि पैं ान। स्वतंत्रता सैनानियों की तहसीलवार तादाद देना मुमकिन नहीं है क्योकि सरकार की तरफ से जो पते दिये गये है, उनमें ज्यादातर केसिज में तहसीलों के नाम दर्ज नहीं है। सरकार इन 1209 अफराद को जो आम स्वतंत्रता सेनानी और साबका आई0एन0ए0 के सदस्य है, माली इमदार दे रही है। इनमें से आम स्वतंत्रता सेनानियों की तादाद 235 और साबका आई0एन0ए0 के सदस्यो की तादाद 974 है। जिलेवार अफराद की तादाद और उनको दी गई रकम की सूचना इसमें दी गयरी है। हम हरियाणा सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली माली इमदाद पर लगभग चार लाख रूपये खर्च कर रहे है।

श्री फतेह चंद विजः मैंने दो साल पहले दो–तीन दफा ि ाकायत की थी कि हमारे यहां सूदन चंद नाम का एक आदमी बोगस सर्टीफिकेट देकर फ्रीडम फाईटर्ज की पैं ान ले रहा है, क्या यह बात मुख्य मंत्री जी की जानकारी में है?

चौधरी देवी लालः इस किस्म की ि ाकायतों के लिये एक कमेटी बनी हुई है, जिसके चेयरमैन आजकल श्री राम भार्मा है। उनके पास ि ाकायतें जाती है। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट इन्कवायरी आदि करने के प चात सरकार के पास भेजती है। जब वह रिपोर्ट आती है तो राज्य सरकार भारत सरकार को अपनी सिफारि ाात के साथ एक ान लेने के लिये भेजती है और भारत सरकार ने एक ान लिया भी है।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया है कि राज्य सरकार भी साबका आई0एन0ए0 के लोगों को और फ्रीडम फाईटर्ज को माली इमदाद देती है इनमें से कुछ को तो आप 25 रूपये महावार देते हो और कुछ को 50 रूप्ये माहवार, यह अन्तर क्यों?

चौधरी देवी लालः राज्य सरकार की तरफ से जो माली इमदाद दी जाती है, उसका बेसिक रेट 25 रूपये महावार ही है लेकिन फ्रीडम फाईटर्ज की बेवा को 30 रूपये महावार दिये जाते है। अलबत्ता कुछ केसिज में मानी हालत और सफरिंग्ज को देखते हुए ज्यादा माली इमदाद दी गयी है जिसका रेट 25, 50, 75, 100, 150 और 200 रूपये महावार तक है। महज 4 केसिज छोड़ कर जिनमें हरियाणा सरकार ने ज्यादा माली इमदाद देने का फैसला किया था बाकी सब केसिज के फैसले ज्वायंट पंजाब के जमाने के है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे इलाके में एक धर्म सिंह नाम का व्यक्ति है, उसको पहले पैं ान मिलती थी, वह बहुत बड़ा फ्रीडम फाईटर भी रहा है, आजादी का कार्यकर्ता भी रहा है। उसकी पैं ान किसी खास वजह से जापेकि मैं हाउस में नहीं बताना चाहता, बंद कर दी गयी है। मैंने इस बारे में कम्पलेंट भी की हुई है, क्या वे उसे दोबारा पैं ान दिलवाने की कोि ा ा करेंगे?

चौधरी देवी लालः अगर ऐसी कोई ि ाकायत है तो वह हमारे पास भेजी जा सकती है। हम उसकी इन्कवायरी कराकर अपनी रिकमैंडे ान भारत सरकार को भेज दें गे और उसे पैं ान दिलवाने की कोि ा ा करें गे।

कंवर राम पाल सिंहः जैसे अभी हाउस में बताया गया है कि कई लोग ऐसे है जो बोगस तौर पर पैं ान ले रहे है, मेरे हल्के में भी दो–तीन आदमी ऐसे है जो बोगस सटीफिकेट देकर पैं ान ले रहे है, क्या सरकार उनके खिलाफ एक ान लेगी?

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्री महोदय ने पहले ही अ योरेंस दे दी है।.....

चौधरी देवी लालः मैं इस बारे में पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जिसके पहले चेयरमैन चौधरी रणबीर सिंह होते थे पहले उनके पास ि ाकायतें आती थी। अब इस कमेटी के चेयरमैंन पंडित श्रीराम भार्मा है। अब ि ाकायते उनके पास आती है। जी कुछ वह हमें रिपोर्ट भेजते है, उसके आधार पर हम अपनी रिकमैंडे ान भारत सरकार को भेज देते है। हमें तो बहुत खु ाी होगी अगर कोई फ्रीडम फाईटर्ज के नाम से गलत तौर पर पैं ान ले रहा हो और वह पकड़ा जाये तो हम मुनासिब सजा देने के लिये उसके खिलाफ एक ान लें गे।

श्री सुरेंद्र सिंहः मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फ्रीडम फाईटर्ज की पैं ान लेने के लिये जो दरखास्तें लेने के लिए डेट मुकर्रर की गयी थी, कुछ लोग उस डेट के दौरान में किसी वजह से अपनी दरख्वास्तें नहीं दे सके थे, क्या सरकार एप्लीके ान्ज री–इन्वाईट करके ऐसे लोगों को पैं ान दने पर विचार करेगी?

चौधरी देवी लालः इसका स्टेट सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत सरकार ने एक डेट मुकर्रर की थी। उस डेट के दौरान मैं जो एप्लीके ान्ज आयीं, हमने भेज दीं। अगर अब भी हमारे पास कोई दरख्वास्त आयेगी तो हम उसे भारत सरकार को भेज देंगे।

श्री सुरेंद्र चंद भट्टः क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 25 रूपये की रकम फ्रीडम फाईटर्ज के लिये नि चत की गयी है, क्या यह उनके साथ एक मजाक नहीं है? क्या उनकी कुर्बानियों को देखते हुए जिसकी वजह से आज हम सब यहां पर बैठे हुए है, उनको और ज्यादा सहूलियात देने पर विचार करेंगे?

चौधरी देवी लालः जो इस किस्म का फैसला हुआ था हरियाणा सरकार ने उस पर भी गौर किया है। आपको मुझे यह बताते हुए हर्श हो रहा है कि पंजाब सरकार के जमाने में जो जमीनें फ्रीडम फाईटर्ज को हिसार के बीड़ में पट्टे पर दी गयी

थी, अब हरियाणा सरकार उनको प्रायरिटी राईटस दे रही है। इसके अलावा भी अगर एम0एल0ए0 साहब कोई खास सजै ान देंगे तो सरकार बड़े हमदर्दाना तरीके से उस पर विचार करेगी और अपनी तरफ से हम पूरी कोि ा ा करेंगे कि भारत सरकार को रिकमेंड करके उनको ज्यादा से ज्यादा मुफाद दिलवाया जाये।

सरदार सुखदेव सिंहः मैं मुख्य मंत्री महोदय ये यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगो को एमरजैंसी के दौरान सरकार ने फ्रीडम फाईटर्ज के सर्टिफिकेट देने चाहे थे लेकिन उन्होंने वह लेने से इन्कार कर दिया था, क्या उसकी सर्विसिज को एप्रीि ाियेट करने के लिए दोबारा से कुछ प्रबंध किया जायेगा? (व्यवधान) मैंने खुद बारह साल अंग्रेजों की कैद काटी है, और मैंने कांग्रेस की सरकार से एमरजैंसी के दौरान में ताम्रपत्र लेने से इन्कार कर दिया था। क्या मुख्या मंत्री महोदय दोबारा से ऐसे लोगों को सर्विसिज को एप्रीि ाियेट करने के लिये कुछ करेंगे?

चौधरी देवी लालः मैं भी आपकी कैटेगरी में आता हूं। मुझे भी ताम्रपत्र पे ा किया गया था लेकिन मैंने भी नहीं लिया। अब पता नहीं कहां पड़े है। अब पता लगाने की कोि ा ा करूंगा कि वे कहां पड़े है और ऐसे लोगों को मान–पत्र और ताम्रपत्र दिलवाने की कोि ा ा करूंगा। इस विशय में जरूर विचार किया जायेगा।

चौधरी हरस्वरूप बूराः जैसे मुख्य मंत्री महोदय ने यह बताया है कि अगर कोई कम्पलेंट आती है तो उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, वह रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजती है, फिर सरकार उस पर अपनी रिकमैंडे ान भारत सरकार को भेजती है, क्या कोई ऐसी कम्पलेंटस आयी भी है?

चौधरी देवी लालः जी हां, वक्तन–फवक्तन आती रहती है और भारत सरकार को हम भेजते रहते है।

लाला बलवंत रायः मैं मुख्य मंत्री महोदय के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि हिसार के बीड़ में जो जमीनें पोनिटीकल सफरर्ज को दी है, उन जमीनों के अन्दर ऐसे ग्रुप्स बन गये है, जो बोगस तौर पर काम करके जमीनें अलाट करवा लेते है और सरेआम घूम रहे है। क्या मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसे केसिज के बारे में जल्दी ही कोई कार्यवाही करेंगे?

चौधरी देवी लालः इसके बारे में मैं भी चाहता हूं कि ऐसे केसिज में एक ान लिया जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि तायल साहब, इसमें सहायता करेंगे। जैसा वे कहेंगे हम करने के लिये तैयार है।

श्री मूलचंद मंगलाः स्पीकर साहब, जिस तरह से फ्रीडम फाईटर्ज ने कश्ट सहे है उसी तरह से एमरजेंसी के दौरान अनेक लोगों को परे ाान किया गया था और जेलों में बिना कसूर के बंद कर दिया गया था लेकिन आज हालत यह है कि उनको रोटी

भी नहीं मिल रही है। क्या मुख्य मंत्री महोदय उनकी सहायता करने के बारे में विचार करेंगे?

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, एमरजेंसी के मरे हुए तो सेन्टर में भी है और स्टेटों में भी राज कर रहे है। इससे ज्यादा पैं ान उनको और क्या मिलनी चाहिए?

मास्टर ि ाव प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्र न के 'ख' भाग के उत्तर में बताया गया है कि सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए है। लेकिन मैंने जो प्र न किया है वह यह है कि जो केस सरकार के ध्यान में आए उनमें अम्बाला जिले के कितने है?

चौधरी देवी लालः स्पीकर साहब, जहां तक अम्बाला जिले का ताल्लुक है मैं अपने मोहतरिम साथी को सारी लिस्ट दे दूंगा और वह पटल पर भी रखी हुई है वे वहां से देख सकते हैं। स्पीकर साहब जो बोगस केसिज की ि ाकायत आई है वह सेन्ट्रल पैं ान लेने वालों से ताल्लुक रखती है। राज्य सरकार से दी जाने वाली माली इमदाद से ताल्लुक नहीं रखती। सेन्ट्रल पैं ान लेने वालों के 49 केस नोटिस में आए है उनकी पैं ान को सस्पेंउ करने के हुक्म भारत सरकार ने कर दिए है।

कामरेड भांकर लालः क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एमरजेंसी के दौरान जो लोग पकड़े गए थे क्या वे तमाम लोग गदि्दयों पर और सरकार के अन्दर रह कर उससे फायदा उठा रहे है?

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहब, इसका एक सबूत तो कामरेड भांकर लाल है जो कभी पहले म्युनिसिपल कमेटी और पंचायत में भी नहीं चुने गए और अब वे एमरजेंसी की वजह से विधान सभा में आ गए है (व्यवधान)

Quota of reservation of posts in the Education Department.

***113. Dr. Brij Mohan Gupta:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the quota of reservation of posts for Ex-servicemen in the Education Department; and

(b) whether the appointments of Ex-servicemen on ad-hoc basis are regularised?

ि ाक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य):

(क) भूतपूर्व सैनिको की सीधी भर्ती के लिए आरक्षण निम्न प्रकार है

श्रेणी–I तथा II 5%

श्रेणी–III तथा IV 25%

(ख) जी नहीं।

डा0 बृज मोहन गुप्ता: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एजुके ान डिपार्टमैंट में चारों केटेग्रीज के कितने कितने एक्स सर्विसमैन है?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, क्लास दो के 12 है, क्लास थ्री के 646 और क्लास फोर के 1025 है।

कई आवाजें: परसेंटेज क्या है यह आप बताइए।

श्री अध्यक्षः मंत्री महोदय ने टोटल नम्बर बता दिया है परसेंटेज आप निकाल लें।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के जवाब में बताया है कि एडहाक बेसिज पर लगाए हुए एक्स सर्विसमैंन को रैगुलर नहीं किया गया है। आज यह हो रहा है कि छः महीने के बाद एक दिन का ब्रेक देकर फिर लगा लिया जाता है। बहुत से लोग तो इस तरह से तीन–तीन, चार–चार साल से काम कर रहे है। क्या मंत्र महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रैगुलर न करने का क्या कारण है?

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, जब एस0एस0एस0 बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमी ान से रैगुलर पोस्ट एडवरटाइज होती है और जो लोग सिलैक्ट किये जाते है उनकी सर्विस रैगुलर होती है। ऐम्पलाएमैंट ऐक्सचेंज के थ्रू लिए हुए लोगों को रैगुलर नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी ऐडहाक बेसिज पर अपांएटमैंट होती है।

कंवर राम पाल सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई रैगुलर पोस्ट ऐडवरटाइज होगी तब उनको रैगुलर कर दिया जायेगा?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, जब कोई रैगुलर पोस्टें निकलेंगी तो उनको रैगुलर करने का ध्यान रखेंगे। स्पीकर साहब असल बात यह है कि ऐक्स सर्विसमैंन के लिए जो पोस्टें है उनके लिए वे क्वालिफिके ांज फुलफिल नहीं करते जिसकी वजह से उनको फुल रिजर्वे ान नहीं मिल रही है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय, ने बताया है कि ऐक्स सर्विसमैन क्लास वन और टू में पांच प्रति ात है और क्लास फोर में पच्चीस परसेंट है और आगे उन्होंने बताया है कि जो क्वालिफिके ांज है उनको ऐक्स सर्विसमैंन पूरा नहीं करते इसलिए पूरी रिजर्वे ान नहीं मिल रही है। स्पीकर साहब, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग है जो क्वालिफिके ांज पूरी करते है और उन्होंने दरखास्तें भी दी हुई है। क्या मंत्री महोदय उनको लेकर इनका कोटा पूरा करने के लिए कोई खास कदम उठा रहे है?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, ऐक्स सर्विसमैंन में बी0ए0 बी0एड0 या जे0बी0टी0 नहीं मिलते इस वजह से पोस्टस वेकेंट है। इस कमी को पूरा करने के लिए एक स्कीम सरकारके विचाराधीन है कि ऐक्स सर्विसमैन के डिपैंडेंट जैसे लड़के या वाइफ को ऐकोमोडेट किया जाए।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, ऐजुके ान डिपार्टमैंट में जे.बी.टी. और बी.एड. टीचर्ज के अलावा भी और

बहुत सी पोस्टें है जिनके ऊपर ऐक्स सर्विसमैंन को लगाया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय उनको दूसरी पोस्टों पर भी लगाने का विचार करेंगे?

हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, उनके लिए जो पोस्टें अवेलेबल होंगी उनको पूरा करने की हम पूर कोि ा ा करेंगे। जो रोस्टर सिस्टम है उसी सिस्टम के मुताबिक पूरा करेंगे।

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, अभी पिछले दिनों ि ाक्षा विभाग में जो चौदह हजार टीचर्ज ऐडहाक बेसिज पर लगे हुए थे उनको रैगुलर किया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो एक्स सर्विसमैंन लगे हुए थे क्या उनकों रैगुलर नहीं किया गया था?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, उनमें जितने भी एक्स सर्विसमैंन आते थे उन सब को रैगुलर कर दिया गया था। इसके अलावा एक्स सर्विसमैंन की 834 पोस्टें है जिनके अगेंस्ट दूसरे आदमी लगे हुए है। इन पोस्टों पर एक्स सर्विसमैंन लगाने के लिए केस विचाराधीन है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, ऐक्स सर्विसमैंन फिजिकली मजबूत होते है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या पी0टी0आई0 का उनका कोटा पूरा किया जाएगा?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, जो क्वालिफिके ान पूरी करेंगे और जितना उनका राइट बनता होगा उसको पूरा किया जाएगा।

डा0 बृज मोहन गुप्ताः स्पीकर साहब, आमतौर पर एक्स सर्विसमैंन पी.टी.आई. की पोस्ट के लिए आते है। कुछ ऐक्स सर्विसमैंन जो जे.बी.टी. टीचर्ज, बी.एड. टीचर्ज और पी.टी.आई. लगे है वे बहुत देर से एडहाक बेसिज पर लगे हुए है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनको रेगुलर कब तक कर दिया जाएगा और उनको रेगुलर न करने में क्या दिक्कत है?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, अगर जे.बी.टी. टीचर्ज की जगह पर अनट्रेंड लोगों को लगा दिया जाये तो ये खुद ही इसके लिए विचार कर सकते है कि क्या हाल होगा।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी मेरे सवाल के जवाब में कहा है कि अदर दैन 14 हजार 834 के केस पैंडिंग है या विचाराधी है। मैं जानना चाहती हूं कि इनको विचाराधीन रखने का क्या कारण है?

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, अपने जवाब में मैंने यह कहा है कि जो 834 पोस्टें है, वे ऐक्स सर्विसमैंन की है और उनके अगेंसट दूसरे आदमी लगे हुये है।

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, जो एक्स सर्विसमैंन का सवाल यहां पर जेरेगौर है, मैं समझता हूं कि यह

काफी जरूरी सवाल है। मैं इसको क्लीयर करना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैंन के लिये कोटा तो मुकर्रर होता है लेकिन उनके लिये अभी सिलैक ान से पहले ट्रेनिंग का कोई साधन नहीं है। हम कोि ा ा करेंगे कि उनको ट्रेनिंग दी जाए। अगर ट्रेनिंग देने का प्रबंध न हुआ तो कोई और रास्ता निकाला जाएगा ताकि उनका रिजवर्ड कोटा उनको मिल सके।

Formation of Kaithal as a District

***1184. Shri Raghu Nath Goyal:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute Kaithal as a district; and

(b) whether the factor of population is also kept in view at the time of consituting a district?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

श्री रघुनाथ गोयलः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कैथल को डिर्स्ट्रकट बनाने का सरकार का कोई विचार है कि नहीं?

श्री अध्यक्षः इस का जवाब मंत्री महोदय दे चुके है

श्री फतेह चंद विजः स्पीकर साहब सवाल के 'क' भाग के जवाब में मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि 'नहीं' इसके लिए सरकार की तरफ से एक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि इन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही यह कैसे कह दिया कि यह मुनासिब नहीं है?

श्री अध्यक्षः विज साहब, मंत्री महोदय ने मुनासिब समझ कर ही ऐसा जवाब दिया होगा।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, पिछली सरकार ने सियासी कारणों की वजह से राजौंद थाने के काफी सारे इलाके को जिला जींद के साथ मिला दिया था। क्या सरकार अब उस इलाके को वापिस कैथल के साथ मिलाकर उसे जिला बनाने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, मैं इसके बारे में क्लीयर करना चाहूंगा कि इसके लिये एक डिस्ट्रिकटस रिआर्गेनाईजे ान कमेटी बनाई हुई है जिसके चेयरमैन चौधरी बीरेंद्र सिह है। वह कमेटी जल्दी ही सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी और फिर आपको पता लग जायेगा कि कैथल जिला बनना है कि नहीं?

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, प्र न के 'क' भाग में यह पूछा गया था कि क्या जिला बनाते वक्त जनसंख्या

को ध्यान में रखा जाता है तो इन्होंने कहा कि सवाल पैदा ही नहीं होता। ऐसा जवाब देकर इन्होंने पार्ट 'क' को 'ख' के साथ जोड़ दिया है। यह तो एक अलग प्र न था। यह एक बड़ा अहम प्र न था कि जिला बनाते वक्त क्या आबादी को भी ध्यान में रखेंगे? आपको जवाब क्लीयर 'हां' में या 'न' में देना चाहिये।

श्री प्रीत सिंहः स्पीकर साहब, इस बारे में तो हमने एक कमेटी बनाई हुई है जोकि इन सारी बातों के बारे में छानबीन कर रही है और उनके पास जो गाईड लाईनज है उसमें यह लिखा हुआ है कि इन बातों का ध्यान रखा जाए–

(i) cultural affinity;

(ii) communication facilites ;

(iii) administrative convenience ; and

(iv) any other relevant factor considered appropriate and expedient.

These are the guidelines before the Committee and it will keep them in view while giving suggestions regarding reorganization of districts.

डा0 बृज मोहन गुप्ताः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जगाधरी को भी जिला बनाने के सरकार की कोई प्रोपोजल है?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भले रामः स्पीकर साहब, गोहाना तहसील काफी बड़ी महसील है। आबादी और पैदावार के लिहाज से भी काफी आगे है। क्या इसको भी जिला बनाने की सरकार के कोई प्रोपोजल विचाराधीन है?

श्री प्रीत सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिये एक कमेटी बनाई हुई है जोकि हर डिस्ट्रकट पर गौर कर रही है। उस कमेटी में कई पब्लिक के रिप्रजेनटेटिवज भी है। अगर कोई अपनी दलील देना चाहे तो वह दे सकता है पर कमेटी जब फाईनल रिपोर्ट सरकार को देगी फिर ही गौर किया जाएगा।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, कालका और नारायणगढ़ का इलाका काफी पिछड़ा हुआ है तो क्या कालका को सब–डिवीजन बनाने की सरकार के कोई प्रोपोजल विचाराधीन है?

श्री प्रीत सिंहः स्पीकर साहब, अगर मेरे साथी कमेटी के सामने अपना केस प्लीड करें तो भाायद ज्यादा अच्छा रहेगा।

Pension and gratuity to the work-charged employess

***1197. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the work-charged employees of Irrigation Department are given the benefits/facilities of pension, gratuity, group insurance, uniform, cycle allowance,

earned leave, leave on medical ground and the National holidays; and

(b) if not, whether the Government will consider giving the said benefits/facilities to the work-charged employees mentioned in part (a) above?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बीरेंद्र सिंह):

(क) वर्क–चार्जड कर्मचारियों को पैं ान, ग्रेच्युटी, ग्रुप इन् योरेंस, अर्जित अवका ा, साईकिल भत्ता और वर्दियों (केवल ड्राइवरों और क्लीनरों को छोड़ कर) का लाभ/सुविधायें नहीं दी जाती है। राश्ट्रीय छुट्टियों और चिकित्सा अवका ा (केवल अस्पताल दाखिल होने पर) की सुविधा दी जाती है।

(ख) वर्क–चार्जड कर्मचारियों जिनका वेतन चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के समान हो, को वर्दी और साइकिल भत्ता देने हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है। अन्य मामलों के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Widening of Roads

***1193. Chaduhri Ishwar Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the roads from Chika to Kaithal and from Chika to Pehowa; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on the

Ghaggar river for providing traffic facilities; if not the measures proposed to be adopted by the Government for providing traffic facilities to the villagers living on the other side of this river?

लोक निर्माण(श्री लछमन सिंह):

(ए) जी नहीं।

(बी) नहीं। तथापि यातायात सुविधा बरास्ता रामनगर–सामाना सड़क से उपलब्ध है। हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब सरकार को ग्राम सारोला (हरियाणा) को चिका–पटियाला सड़क पर ग्राम धमरेरी (पंजाब) से छोटे रास्ते से मिलाने के लिये कहा जा रहा है।

चौधरी ई वर सिंहः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि 'नहीं' जबकि पंजाब से आने जाने का यह एक रास्ता है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए दोबारा विचार किया जाएगा और इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, सड़कों को चौड़ा करने के लिये कोई क्राईटेरिया भी होता है और इस सड़क के लिये ऐसी कोई नसैसिटी नहीं है कि इस को चौड़ा किया जाए।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, कई सड़कों पर एकदम 45 डिग्री के कोण के बराबर मोड़ होते है और सड़क के

दोनों तरफ बड़े–बड़े दरख्त लगे हुये होते है जिसकी वजह से दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। क्या इस चीज को ध्यान में रखतें हुए सरकार दोनों तरफ से दरख्त हटाने पर विचार करेगी ताकि एक्सीडैंटस से लोगों को बचाया जा सके?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, किसी पर्टिकुलर सड़क का नाम आनरेबल मैम्बर बता दें। अगर वाकई कोई ऐसा मोड़ होगा तो उसको ठीक करवा देंगे।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः स्पीकर साहब, मेरे हल्के में कई बे–चिराग मौजा है जैसे कुतान, सराय अहमद, नसीपुर वगैरह, इनमें सड़कें बनाई जा रही है जबकि वहां सड़क की जरूरत नहीं। क्या सरकार ऐसा कोई विचार रखती है कि वहां पर सड़क बनाने की बजाये छछरौली में सड़क बनाई जाए,

10:00 बजे

श्री अध्यक्षः यह सवाल तो चीका और कैथल की सड़कों को चौड़ा करने के संबंध में है।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः स्पीकर साहब, अगर कोई काम की बात आये तो उसे मान लेना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बे–चिराग मौजा है जैसे कुताना है, नसीरपुर है, पाड़ा है और सराय अहमद है इन में सड़क बनाने के लिये 34 किल्ले जमीन ली जा रही है जबकि वहां पर सड़क की जरूरत

नहीं है। तो इसकी बजाये छछरौली जहां 14 किल्ले जमीन से सड़क मिल सकती है, वहां पर सड़क बना दी जाये।

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी ई वर सिंहः अभी मंत्री जी ने बताया कि चीका से पटियाला जाने के लिये समाना रोड वाया राम नगर से रास्ता उपलब्ध है। यह रास्ता इन्होंने पंजाब का बताया है परन्तु इन्होंने जो ग्राम सारोला (हरियाणा) को और ग्राम धमरेरी (पंजाब) को छोटे रास्ते से मिलाने के लिये कहा है उसके लिये कितना समय लगेगा? क्या इसके लिये कोई नि चित समय बातएंगे?

श्री लछमन सिंहः मैं दूसरी स्टेट के बारे में कैसे बता सकता हूं कि कितना समय लगेगा। फिर भी हम को ि ा ा करेंगे कि वह सड़क जल्दी बन जाये और मेरा ख्याल भी है कि पंजाब वाले उस सड़क को जल्दी बना देंगे। मैं मैम्बर साहब को कहूंगा कि ऐसे काम के लिए वे खुद भी थोड़ी सी को ि ा ा कर लिया करें।

लाला बलवंत राय तायलः क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि सड़कों को चौड़ा करने का क्या काइटेरिया है?

श्री लछमन सिंहः इस संबंध में एक काल अटैन ान मो ान आया था उस वक्त मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। मैं फिर बताना चाहता हूं कि सड़कों को चौड़ा करने का काइटेरिया यह है कि जब किसी सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाये तो उसे

चौड़ा कर दिया जाता है अगर ट्रैफिक नार्मल हो तो सड़क चौड़ी नहीं की जाती।

श्री लहरी सिंह मेहराः अभी मंत्री महोदय ने बताया कि अगर ट्रैफिक ज्यादा हो जाये तो सड़क चौड़ी कर दी जाती है तो मैं जानता हूं कि अगर ट्रैफिक कम हो जाये तो क्या सड़क भीड़ी कर दी जाती है? (हंसी)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले दिनों हर एम0एल0ए0 के पास सरकार की तरफ से एक लैटर गया था कि हर एम0एल0ए0 पांच किलोमीटर सड़क अपनी मर्जी से कहीं भी बनवा सकता है तो क्या वह हुक्म अब भी बरकरार है या नहीं?

श्री लछमन सिंहः यह तो चीकर और कैथल की सड़कों का सवाल है, इससे इस सवाल का कोई संबंध नहीं है।

चौधरी गंगा रामः अभी मंत्री महोदय बता रहे थे कि सड़कों को चौड़ी करने का मामला ट्रैफिक पर निर्भर करता है इन्होंने कहा कि ट्रैफिक ज्यादा हो जाये तो सड़क चौड़ी कर दी जाती है और ट्रैफिक कम हो जाये तो सड़क भीड़ी कर दी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये काठ की सड़कें या रबड़ की सड़कें बनायेंगे जो जरूरत के अनुसार कभी चौड़ी कर दी जायें और कभी भीड़ी कर दी जायें?

श्री लछमन सिंहः मैंने यह नहीं कहा कि अगर ट्रैफिक कम हो जाता है तो सड़क भीड़ी कर दी जाती है। स्वामी जी मेरे गले पड़ रहे है। लड़की कोई मानती नहीं और भाादी का प्रबंध किया जा रहा है। (हंसी)

चौधरी हरस्वरूप बूराः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुछ सड़कें जो गांवों के पास से निकलती है उनके साथ तालाब भी लगते है। वहां से प ा बहुत गुजरते है जिस वजह से सड़कें जल्दी टूट जाती है तो क्या ऐसी सड़कों के दोनों तरफ रिटेनिंग वाल लगाई जाएगी?

श्री लछमन सिंहः ऐसी सड़कों पर तो हम पहले ही रिटेनिंग वाल लगाते है।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि सड़कों के साथ जो कच्ची मिट्टी डाली जाती है उस पर अगर बस का पहिया आ जाता है तो बसों का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर नर्म जमीन होती है तो क्या इन दिक्कत को देखते हुए सड़कों को चौड़ा किया जाएगा?

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भले रामः कई सड़कें गांव के बीच में से निकली हुई है और वहां पर लोगों की जमीन का झगड़ा है तो क्या ऐसी जगहों पर बाई पास बनाया जाएगा?

श्री लछमन सिंहः अभी तक तो कोई ऐसा बाई पास निकालने की जरूरत महसूस नहीं हुई है अगर मैंबर साहब कोई पर्टिकुलर मु कलात बताएंगे तो गौर किया जा सकता है।

चौधरी पीर चंदः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि दिल्ली से अम्बाला ओर दिल्ली से फिरोजपुर जो सड़कें जाती है क्या इनकों चौड़ा किया जाएगा?

श्री लछमन सिंहः मैंने एक काल अटैं ान मो ान के जवाब में बताया था कि एक सड़क जो नगलोई से बहादुरगढ़ तक की है उसका आज उद्घाटन हो रहा है। जहां तक दिल्ली अम्बाला रोड़ का ताल्लुक है इस बारे में केस गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास गया हुआ है। मुझे आ ाा है उसकी क्लियरैंस हो जाएगी। यह सड़क एकदम चौड़ी नहीं हो सकेगी बल्कि फेजिज में चौड़ी होगी।

श्री गुलजार सिंहः स्पीकर साहब, कई सड़कें जिलों की रि–आर्ग्रेनाइजे ान होने से पहले बनाई गई थी। जैसे राजौंद हल्का पहले जिला करनाल में था और वहां पर उसी हिसाब से सड़कें बनी हुई थी। लेकिन आज उस हल्के के कुछ गांव जिला जींद में जाने की वजह से तीस मील का चक्कर काटना पड़ता है तो क्या इस दिक्कत की तरफ भी कोई ध्यान दिया जाएगा?

श्री लछमन सिंहः जींद के तो चारों और एक सर्कुलर रोड़ बन रही है।

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): आनरेबल मैंबर ने जो दिक्कत बताई है वह एक जगह नहीं बहुत जगहों पर है। पहले जिले ऐसे ढंग से बनाये गये थे जिन्हें बदलने के निये अब एक कमेटी बैठी है। वह कमेटी जिलों की एडजस्टमैंट करेगी लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह गई तो जिलों और तहसीलों को मिलाने की पूरी कोि ा ा की जाएगी ताकि लोगों को तकलीफ दूर की जा सके।

Shortage of Teachers in Education Department

***901. Swami Adityavesh:** Will the Minister of Education be pleased to state-

(a) whether it is a fact that at present there is shortage of J.B.T. teachers, Shashtri teachers, Science teachers and Mathematics teachers in the Education Department ; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons therefore?

ि ाक्षा मंत्री(श्री हीरा नंद आर्य):

(क) (i) जी नहीं, जे.बी.टी. अध्यापकों की कोई कमी नहीं है।

(ii) लेकिन भाास्त्री, विज्ञान तथा गणित अध्यापकों की निर्धारित योग्यताओं के साथ कुछ कमी है।

(ख) वर्श 1973 की अध्यापक हड़ताल के समय जो स्टाईपैंडरी ि ाक्षक भर्ती किए गए थे तथा जो सामाजिक अध्ययन ि ाक्षक युक्तिकरण के कारण फालतू हो गए थे, उन्हें भाास्त्री, विज्ञान तथा गणित अध्यापकों के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया गया था।

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैं मान्यवर मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन्होंने स्वीकार किया कि गणित, भाास्त्री और विज्ञान के अध्यापकों की कमी है, और ये इस कमी को सामाजिक भाास्त्र आदि अध्यापकों से पूरा करते है। अध्यक्ष महोदय, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं, विज्ञान की जानकारी नहीं और गणित की जानकारी नहीं वह कैसे इन विशयों को पढ़ा सकता है?

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछिए, सुझाव मत दीजिए।

स्वामी आदित्यवे I: मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि इन विशयों में अध्यापकों की कमी है तो क्या इस कमी को इसी विशय के अध्यापाकों द्वारा पूरा किया जायेगा?

श्री हीरा नंद आर्य: अध्यक्ष महोदय मैंने बताया है कि इन विशयों के अध्यापकों की कमी है। अगर स्वामी जी बाहर से भी ऐसे अध्यापक ले आएं तो हम विचार कर लेंगे।

चौधरी सरदार खांः मैं वजीर साहब से जानना चाहूंगा कि कुछ जे.बी.टी. टीचर्ज को परमानेंट करने के लिए सिलैक ान हो गया है लेकिन इस सिलैक ान में नहीं आये है और अभी तक सिक्स मंथ बेसिज पर काम कर रहे है उनके बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री हीरा नंद आर्यः सिक्स मंथ बेसिज पर अकेले जे. बी.टी. अध्यापक ही नहीं है और भी है। उनके लिए सरकार विचार कर रही है।

श्री भले रामः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पीछे जो स्कूल अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाये गये थे उनमें संस्कृत अध्यापकों की पोस्टें नहीं है इसलिए वहां संस्कृत पढ़ाने की समस्या है। क्या उन स्कूलों में संस्कृत अध्यापकों की पोस्टें बनाई जायेगी?

श्री हीरा नंद आर्यः अगर वहां संस्कृत अध्यापकों की जरूरत होगी तो संस्कृत अध्यापकों की पोस्टें जरूर दी जायेंगी।

श्री अध्यक्षः संस्कृत कोई कम्पलसरी सब्जैक्ट नहीं है, कोई पढना चाहे तो उसको पढ़ाया जाता है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया कि वे इस कमी को दूसरे अध्यापकों से पूरा करते है। अगर पंजाबी टीचरों की कमी को भी इसी तरह पूरा

करते है तो क्या इस कमी को पूरा करने के लिए पंजाबी टीचर्ज बाहर से लिए जाएंगे?

श्री अध्यक्षः क्या मंत्री महोदय पंजाबी टीचर्ज के बारे में कहना चाहेंगे कि किस प्रकार इस कमी को पूरा किया जायेगा?

श्री हीरा नंद आर्यः इन कई किस्म के अध्यापकों की जगह एस0एस0 मास्टर्ज लगे हुए है। जैसे संस्कृत के 84, मैथ्स के 207 पंजाबी के 56, हिंदी के 88 मास्टर्ज लगाये गये है। इन अध्यापकों के न मिलने की वजह से ि ाक्षा देने में कठिनाई होती है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः मंत्री महोदय ने जवाब में फरमाया कि जहां बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहेंगे वहां संस्कृत टीचर की पोस्ट क्रियेट की जायेगी। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि संस्कृत सब्जैक्ट ही जहां न हो तो वहां बच्चों की इच्छा को कैसे असरटेन करेंगे।

श्री अध्यक्षः यह पालिसी मैटर है।

चौधरी संत कंवरः मंत्री महोदय, ने अपने जवाब में कहा है कि गणित के अध्यापकों की कमी है। मैं बताना चाहता हूं कि इनकी कमी नहीं है। हरियाणा में बहुत से टीचर्ज ऐसे है जो सिक्स मंथ बेसिज पर कई सालों से गणित के अध्यापक चले आ रहे है वे एक दिन की भी छुट्टी नहीं जा सकते है अगर जाते है

तो उनकी तनख्वाह काटी जाती है। क्या इन अध्यापकों को रैगुलर करने पर विचार किया जाएगा ताकि यह कमी दूर हो सके?

श्री अध्यक्षः इसका जवाब मंत्री महोदय ने दे दिया है कि इनको दूसरी पोस्टों के अगैंस्ट रखा हुआ है। जब पोस्टें होंगी तो इनको रैगुलर किया जाएगा।

चौधरी संत कंवरः इन अध्यापकों को परमानैंट क्यों नहीं किया गया?

श्री हीरा नंद आर्यः छः महीने के बेसिज पर और भी लगे हुए है जिनको एक दिन का ब्रेक भी नहीं दिया जाता। ये रिजर्व पोस्टों के अगैंस्ट लगाये हुए है इनको रैगुलर करने के लिए मामला विचाराधीन है।

श्रीमती भाान्ति देवीः कई स्कूलों में बच्चे ड्राईंग करना नहीं चाहते है लेकिन वहां पर ड्राइंग टीचर्ज है। लेकिन जिस स्कूल में बच्चे संस्कृत के अध्यापक की पोस्ट नहीं है तो क्या संस्कृत टीचर्ज की पोस्टें जल्दी दी जाएगी?

श्री हीरा नंद आर्यः जहां पोस्टें नहीं है, आप बता दें, हम देने की कोि ा ा करेंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः जैसा कि वजीर साहब ने बताया कि कई सबजैक्टों के लिए एस0एस0 मास्टर्ज लगाये हुए है। इस सरकार को कहते हुए दो साल हो गये कि मजबूरी है

यह मजबूरी कब दूर होगी और कब तक हर सबजैक्ट के लिए टीचर लगाये जाएंगे? यह बड़ा अहम सवाल है इसलिए इस पर विचार करने के लिए अलग से आधे घंटे का टाईम दिया जाए।

श्री अध्यक्षः पोहलू साहब, आप बैठ जाइयें।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने जनता सरकार में मंत्री बनने के बाद ऐसी कोई नीति, कोई रोस्टर या कोई रूल बनाया है कि इस सिस्टम को बदला जा सके?

श्री अध्यक्षः यह पालिसी का सवाल है इसलिए यह सवाल इससे संबंधित नहीं है।

चौधरी सरदार खांः स्पीकर साहब उर्दू को सभी समझते है इसलिए उर्दू टीचर लगाने के बारे में वजीर साहब क्या विचार कर रहे है?

श्री हीरा नंद आर्यः उर्दू का इस सवाल से कोई संबंध नहीं है इसके लिए अलग नोटिस दें।

श्री सुरेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हुड्डा साहब ने पूछा कि हरियाणा में जनता सरकार बनने के बाद (विघ्न)

Mr. Speaker: What policy the Janata Government is going to make about education is not under discussion.

Shri Surrender Singh: That was a promise in their election manifesto.....

Mr. Speaker: It may be. But that is not under discussion. You can ask a question, if you so like.

श्री सुरेंद्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जनता सरकार के बनने के बाद एजुके ान में कोई रेडीकल चेंज लाई गई है?

श्री अध्यक्षः इसका सवाल से कोई संबंध नहीं है। This has got no concern with the question.

चौधरी भाकरूल्लाः उर्दू के लिए पीछे मुख्य मंत्री जी ने एलान किया था कि जो मौलवी मस्जिदों में उर्दू पढ़ाते है उन्हें ही उर्दू टीचर के लिए लगा लिया जायेगा। क्या इस पर विचार किया गया है?

श्री हीरा नंद आर्यः इस सवाल को इससे कोई संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर वे क्वालीफाईड टीचर होंगे तो उनको जरूर लिया जायेगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, जैसे मंत्री जी ने फरमाया है कि भाास्त्री टीचर्ज और सांइस टीचर्ज की वाकई में कमी है तो सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदन उठाए है?

श्री अध्यक्षः आधा घंटा इस बात पर बहुस हुई है और आप बार–बार वही क्वै चन पूछ रहे है।

सरदार तारा सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि करनाल और कुरूक्षेत्र जिले में पंजाबी की क्लासिज भ्रुरू नहीं की जा रही है और हैड मास्टर साहेबान यह कहते है कि हमारे पास पंजाबी मास्टर नहीं है। क्या मिनिस्टर साहब एक सर्कुलर निकलवा कर पता करवाएंगे कि कौन कौन से स्कूल ऐसे है जहां पंजाबी क्लास के लिए स्टुडैंटस है और वहां पंजाबी मास्टर न होने की वजह से पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती?

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सवाल के लिए अलग से नोटिस चाहिए लेकिन जहां पर 10 बच्चें पंजाबी पढ़ने वाले मिलते है तो उनके लिए हम पंजाबी टीचर्ज प्रोवाइड करते है।

श्री अध्यक्षः पंजाबी, उर्दू और संस्कृत के बारे में सरकार की क्या पालिसी है वह आप इनकों बता दीजिए।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, जहां दस बच्चे इनमें से किसी भाशा को पढ़ना चाहें वहां पर उस भाशा का टीचर प्रोवाइड किया जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः सरदार जी, मिनिस्टर साहब ने बताया है कि जिस स्कूल में दस बच्चे पंजाबी, उर्दू और संस्कृत पढ़ना चाहें उनके लिए सरकार टीचर्ज की व्यवस्था करेगी।

सरदार तारा सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि पढ़ने वाले लड़के तो है लेकिन हैड मास्टर यह कह रहे है कि हमारे पास पंजाबी मास्टर नहीं है?

मुख्य मंत्री(चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, हमने पंजाब गवर्नमैंट को लिखा है कि हमें 50 टीचर्ज पंजाबी के भेजे ताकि हम उनकी सर्विसिज यहां पर युटिलाइज कर सकें लेकिन मुकामी पंजाबी बोलने वाले भाईयों ने कहा कि बाहर से न मंगवाएं, यहां पर भी मिल जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर यहां से मिल सकते है तो हम लेने के लिए तैयार है। हमें तो टीचर चाहिएं इसके अलावा जहां भी उर्दू के लिए टीचर्ज की मांग होगी वहां उर्दू टीचर्ज का भी प्रबंध करेंगे और अगर यहां पर नहीं होंगे तो हम पंजाब से भी मंगवा करकें देंगे।

श्री हीरा नंद आर्यः अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि पंजाब गवर्नमैंट को लिखा गया था। पंजाब गवर्नमैंट का जवाब आ गया है कि हमारे पास ट्रेंड पंजाबी मास्टर स्पेयर नहीं है।

स्वामी आदित्यवे ाः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रान्त मैं भाास्त्री, गणित और विज्ञान के टीचर्ज की बहुत कमी है तो मैं

पूछना चाहता हूं कि यह कमी कितनी है और इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, आप तो कन्फयूज हो रहे है इसका जवाब तो गवर्नमैंट बहुत अच्छी तरह से दी चुकी है।

तारांकित प्र न संख्या 1181

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री भाम ोर सिंह, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे–

Instructions issued for making appointments in the Cooperative Sector.

***1138. Dr. Brij Mohan Gupta;**

Shri Fathe Chand Vij

Shri Raghu Nath Goyal:

Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) whether the Government have issued any instructions to the Cooperative Sector for making new appointments through the Employment Exchange;

(b) whether any complaint has been received by the Government that the new appointments have been made by them directly without calling the names of the candidates from the Employment Exchanges; and

(c) if so, the action taken thereon?

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां जी। परन्तु कुछ सहकारी सस्थाओं के सेवा नियमों में विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती का भी प्रावधान है।

Put by Dr. Brij Mohan Gupta.

(ख) हां जी।

(ग) इन ि ाकायतों की जांच हो रही है।

डा0 बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल तो यह पूछा था कि क्या सरकार की ऐसी इंस्ट्रक ांज है कि कोई भी भर्ती एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के जरिए करेंगे तो उन्होंने कहा 'यैस' लेकिन आगे 'बट' क्यों लिखा हुआ हे यह बात मेरी समझ में नहीं आती इसका क्या मतलब है?

श्री अध्यक्षः यह बात तो बड़ी साफ है कि सवाल का जवाब सिर्फ 'यै ा' और 'नो' में ही नहीं होता बल्कि कभी–कभी उन्हें एक्सप्लेनेटरी नोट भी देना पड़ता है। इसलिए यह तो बड़ी सीधी सी बात है।

श्री भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 'बट' के बारे में उन्होंने कहा है, उसके बारे मे मैं बताना चाहूंगा कि पंजाब सोसाइटीज एक्ट 1961 जो हरियाणा सरकार ने 1972 के अधिनियम 22 द्वारा लागू किया है इसकी धारा 84–ए में कामन

काडर रूल बनाया गया है कि किसी भी एक दैनिक प्रमुख पत्र में विज्ञापन द्वारा भर्ती की जा सकती है।

श्री फतेह चंद विजः अध्यक्ष महोदय, 'सी' के जवाब में इन्होंने कहा है कि इन्कवायरी हो रही है। क्या सरकार इंक्वायरी वाले मैथड को कुछ भाार्ट करेगी ताकि जल्दी से जल्दी ऐसी नाजायज भर्तियां रोकी जा सकें। इनकी इंक्वायरी के दौरान जो और भर्ती हो रही है उसे रोकने के लिए इन्होंने क्या प्रबंध किया है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार ने इस बारे में महकमें को लिखा हुआ है कि वह एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के थ्रू भर्ती करें। दूसरा इसमें आता है कोआप्रेटिव अदारा वह इनडिपैंडैंट बाडी है और उसमें हमने यह फैसला किया है कि वे 50 परसैंट एम्पलायमैंट एक्सचेंज से नाम मांगे और 50 परसैंट अखबारों में एडवरटाइज करके एप्लीके ांज इनवाइट करें फिर उसके बाद इन्टरव्यू ले करके भर्ती करे।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, प्र न के भाग 'क' में जवाब आया है–

''परन्तु कुछ सहकारी सस्थाओं के सेवा नियमों में विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती का प्रावधान है'' मैं सहकारिता मंत्री जी

से जानना चाहती हूं कि वे सहकारी संस्थाएं कौन कौन सी है जिनमें सीधी भर्ती का प्रावधान है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, 'हरको बैंक', लैण्ड डिवैल्पमैंट बैक्स और सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक्स है जिनमें इस तरह का प्रावधान है।

चौधरी गया लालः अध्यक्ष महोदय, रोजगार विभाग में बहुत से बच्चों कै दो–तीन साल से नाम लिखें हुए है लेकिन कई विभाग डायरैक्ट भर्ती कर लेते है क्या इस पर कोई रोक लगाई जाएगी कि वे डायरैक्ट भर्ती न करें और यह जो 50 परसैंट डायरैक्ट लिये जाते है वह भी रोजगार विभाग से लिए जा सकते है तो मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि वह रोजगार विभाग से क्यो नहीं लिए जाते?

श्री अध्यक्षः यह तो गवर्नमैंट की पालिसी है। मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि 50 परसैंट थ्रू एडवरटाईजमैंट लिए जाएंगे तो जिनके नाम रोजगार विभाग में दर्ज है वे भी अपना नाम एडवरटाइजमैंट के थ्रू निकली पोस्टों के लिए दे सकते है, इसमें कोई एतराज नही है।

श्री रघुनाथ गोयलः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हैफेड में जो कर्मचारी रखे गए है वे एम्पलायमैंट के थ्रू रखे गए है या डायरैक्ट रखे गए है?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इस अपैक्स बाडी में 19 कर्मचारी रखे गए है उनके बारे में हमने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है और यदि किसी ने गल्त तरीके से रखें होंगे तो उस पर हम जरूर कार्यवाही करेंगे।

चौधरी राजेंद्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में सैंट्रल कोआप्रेटिव बैंक के अन्दर काफी समय से रिक्त स्थान पड़े हुए है और उन स्थानों पर नियुक्ति न करने की वजह से बैंक के अन्दर काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उस बैंक को भीघ्र ही कोई ऐसी इंस्ट्रक ान देंगे ताकि उन रिक्त स्थानों को जल्दी से जल्दी भर दिया जाएं?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां भी पोस्टें खाली है उनके लिए हमने सभी बैंकों को लिख दिया है कि वे जल्दी से जल्दी अपनी भर्ती पूरी करें ताकि सरकारी या जनता के कामों में कठिनाई न हो जितनी भी पोस्टें खाली है उनको भरने के लिए कार्यवाही भुरू कर दी गई है।

चौधरी लाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री जी अपने महकमें का सुधार कर रहे है तो मैं आपकी मारफत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने नान–मैट्रिक बिना एम्पलायमैंट एक्सचेंज के जो मिनि बैंक मैनेजर भर रखें है उनका क्या होगा?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, स्टेट में मिनि बैंक मैनेजर कोई भी नान–मैट्रिक नहीं है क्योंकि मैट्रिक से ऊपर या मैट्रिक तक के ही आदमी मिनि बैंक मैनेजर लगते है (ाोर) माननीय सदस्य एक भी अगर ऐसा नाम बता दें कि कहीं भी स्टेट में मिनी बैंक का मेनेजर नान–मैट्रिक आदमी लगा हुआ है तो मैं उसको लगाने वाले अधिकारी के खिलाफ भी एक ान लूंगा और उस कर्मचारी को भी फौरान हटा दिया जाएगा लेकिन ऐसी बात न है और न ही हो सकती है।

Mr. Speaker: The question is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Agreement between the employees of Panipat Cooperative Sugar Mills and Management Board.

***1198. Comrade Shankar Lal:** Will the Minister for Cooperation and Dairy Development be pleased to state-

(a) whether any agreement was reached under section 12(3) of the Industrial Disputes Act in 1964 between the employees of Panipat Cooperative Sugar Mills and the Management Board;

(b) whether it is also a fact that the employees of the said Mill have been getting their pay and dearness allowance since 1964 on the basis of the above said agreement; and

(c) whether the Management Board of Panipat Sugar Mills, Panipat has yet to implement any award in respect of pay and allowances?

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री(चौधरी भजन लाल):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

Bridge on Patiala Rivulet

***1194. Chaudhri Ishwar Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Government propose to construct a bridge on the Patiala Rivulte near the Malikpur village situated on the other side of Ghaghar ; if so, the time by which it is likely to be constructed; and

(b) the number of distributaries on which the lining work is likely to be done in Gulha tehsil togetherwith the time by which the said work is likely to be completed?

Irrigation and Power Minister(Shri Verender Singh):

(a) No.

(b) 19 distributaries and Minors are proposed to be lined under the programme of modernisation of channels in Gulha tehsil and the entire work is proposed to be completed

in 12 years. Out of these, work on 5 distributaries is proposed to be complete in the 1st phase to be completed by June, 1982.

Loanees of the Co-operative Socities

***922. Swami Adityavesh:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether it is in theknowledge of the Government that the loanees of the Cooperative Societies have repaid the loans advanced to them but the officers concerned have not cleard their accounts so far ;

(b) if so, the number of such Cooperative Societies; and

(c) the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government against the officers who have not adjusted the amount as referred to in part (a) above?

Cooperation and Dairy Development Minister(Chaudhri Bhajan Lal):

(a) Yes.

(b) Number of such Cooperative societies is 229.

(c) There are 280 cases in these societies in which officers are involved. Following action has been taken/is being taken in respect of these cases.

(i)	Cases with the Police under investigation:	65

(ii)	Cases pending with Courts	25
(iii)	Cases referred for arbitration under Cooperative Societies Act.	72
(iv)	Under process with Department/Central Cooperative Banks	118
	Total	280

स्वामी आदित्यवे I: अध्यक्ष महोदय, मैंने 23 तारीख को हरियाणा भवन दिल्ली में हुई घटना के बारे में एक काल अटैं ान मो ान दिया था.....

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

Mr. Speaker: Order please, please take your seats. (Interruptions) अगर आप लोगों को हाउस की डिगनिटी मेंटेन करनी है तो जब स्पीकर बोलने के लिए खड़ा हो तो आप उसे सुनने का कश्ट किया करें। (व्यवधान) स्वामी जी का काल अटैं ान मो ान मुझे मिला था, उसको बाकयदा स्टडी किया गया उस पर गौर करने के बाद उसे डिस–अलाउ कर दिया और उसकी सूचना आपके पास पहुंच गई है। इस मामले में दोबारा हाउस में रेज करने का कोई रूल नहीं है। स्पीकर की रूलिंग

आने के बाद इस पर कोई डिसक ान नहीं हो सकती। (व्यवधान) अब इस पर अगर कोई डिस्क ान होगी तो उसको रिकार्ड न किया जाए।

स्वामी आदित्यवे ाः

****

श्री अध्यक्षः अब मैं पब्लिक अकाउंटस कमेटी के चेयरमैन से कहूंगा कि वे अपनी रिपोर्ट पे ा करें।

चौधरी उदय सिंह दलालः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब मैं आपसे प्रााार्थना करूंगा कि स्वामी जी और दूसरे मैम्बर साहेबान जो बोल रहे है, मैं इनका अहतराम करता हूं लेकिन इनको बोलने का लाइसेंस न दें। हाउस में सबसे ज्यादा सवाल ये करते है सबसे ज्यादा टाईम ये लेते है और मो ान्ज वगैरा इनकी सबसे ज्यादा होती है लेकिन न ये अपने हलके में जाते है और न ही कोई काम करते है। इनको इतना ज्यादा न बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हरफूल सिंहः स्पीकर साहब, ये बार–बार हाउस की कार्यवाही के अन्दर बगैर किसी मतलब की बात के, दखल देते है, मेरा ख्याल है इनको हाउस से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

(इस समय स्वामी आदित्यवे ा फिर बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्षः स्वामी जी, आप त ारीफ रखिए (व्यवधान) अब कंवल सिंह जी अपनी रिपोर्ट पे ा करेंगे।

चौधरी गंगा रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, हम इस बात को मानते है कि एक दफा जब चेयर की रूलिंग आ जाए तो किसी मैम्बर को उस पर डिस्क ान करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपकी रूलिंग आ चुकी है इसके बाद भी अगर वे कोई एतराज करते है, डिसक ान करते है हाउस को चलने नहीं देते तो मैं कहूंगा कि ऐसे मैम्बर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक ान लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए मैम्बर साहिबान, इस विशय पर मैंने अपनी रूलिंग दे दी है और मैं सब सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि अगर किसी मैम्बर ने मेरी रूलिंग के बारे में कोई बात करनी है तो वह कृपया मेरे चैम्बर में आकर बात कर ले। हाउस के अन्दर मेरी रूलिंग के बारे में कतई डिस्क ान नहीं हो सकती। (व्यवधान) अब श्री कंवल सिंह रिपोर्ट पे ा करेंगे। (व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे ाः

**************************************(विघ्न)**

श्री अध्यक्षः मेरी रूलिंग के बारे में जो बात कही जाए, वह रिकार्ड की जाए।

Voices: * * * * * * * *

श्रीमती भाान्ति देवीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, सरकार का यह निर्णय है कि जिस पंचायत से, भाराब का ठेका न खोलने के बारे में रैजोल्यू ान आ जाए, वहां ठेका नहीं खोला जाएगा।

श्री अध्यक्षः यह प्वायंट आफ आर्डर नहीं।

श्रीमती भाान्ति देवीः आप मेरी बात तो सुन लीजिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः साहेबान, दो काल अटैं ान मो ान एडमिट हो चुके है जिनकी मंत्री महोदय जवाब दे चुके है। अगर फिर भी आपको कोई एतराज है, किसी चीज की क्लैरिफिके ान लेना चाहते है तो आप एक काल अटैं ान मो ान और दे सकते है, उसको एग्जामिन कर लेंगे।

अब श्री कंवल सिंह जी लोक सेवा समिति की रिपोर्ट पे ा करेंगे।

पब्लिक अकाउंटस कमेटी की तेहरवीं रिपोर्ट पे ा करना

श्री कंवल सिंह(सभापति, लोक लेखा समिति): मैं राजस्व विभाग के बारे में वर्श 1973–74 के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की अनुपूरक रिपोर्ट पर वर्श

1978–79 के लिए हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति की तेरहवीं रिपोर्ट पे ा करता हूं।

वर्श 1979–80 के लिए बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष: अब वर्श 1979–80 के बजट की डिमांडज फार ग्रांटस पर बहस होगी और इसके साथ मतदान भी होगा। पहले से चली आ रही प्रैक्टिस के मुताबिक सदन का समय बचाने के लिए, आर्डर पेपर पर रखी गई, सब डिमांडज फार ग्रांटस एक साथ पढ़ी गई तथा पे ा की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते है, लेकिन बोलते समय जिस डिमांड पर बोलना चाहते है उसका नम्बर बता दें। 12–30 बजे गिलोटीन एप्लाई किया जाएगा।

कि 34,74,000 रूपये से अनधिक धन–रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 1–विधान सभा के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 4,31,98,990 रूपए से अनधिक धन–रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 4– राजस्व के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 2,30,71,560 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 5– उत्पाद भाुल्क तथा कर के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 5,01,92,085 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 6– वित्त के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 3,80,73,430 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 7– अन्य प्र ाासनिक सेवाएं के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 38,05,94,160 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 8– भवन तथा सड़कों के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 1,24,98,310 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 11– नगर विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 6,29,38,310 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 13– कल्याण तथा पुनर्वास के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 95,02,08,800 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 14– खाद्य एवं सप्लाई के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 71,54,350 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 19– मछली पालन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 3,9871,940 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 20– वन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 33,22,260 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 24– पर्यटन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम मैं आयेंगे।

कि 58,25,00,500 रूपए से अनधिक धन–रा ि। राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 25– राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्जों तथा पे ागियों के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के कम में आयेंगे।

चौधरी बीरेंद्र सिंह(उचाना कलां): स्पीकर साहब, आज जो डिमांडज सदन में रखी गई है.....

डा0 बृज मोहनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, टाईम लिमिट रख दें तो अच्छा रहेगा, ऐसा करने से सब मैम्बर बोल सकते है।

श्री अध्यक्षः यह बहुत अच्छी सुजै ान है। अगर हाउस की सैंस है तो 5–5 मिनट फी मैम्बर के लिये टाईम फिक्स कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैम्बर डिस्क ान में हिस्सा ले सकें।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः 10 मिनट से कम टाईम नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

कई सदस्यः 5 मिनट काफी है। 5 मिनट को टाईम रखने से बहुत से सदस्य बोल सकते है।

श्री अध्यक्षः चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आपको दो मिनट फालतू दे दूंगा, लेकिन मजोरिटी 5 मिनट के हक में है, इसलिए we will stick to 5 minutes.

चौधरी बीरेंद्र सिंहः स्पीकर साहब, आज सदन में जो डिमांडज रखी गई है, इन में से डिमांड सं0 1, 5, 7, 8 तथा 25 पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। डिमांड संख्या 7 में 3,80,73,430 रूपये की रा ि ा रखी गई है जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज के हैड के नीचे है। इस हैड में हरियाणा भवन दिल्ली, होसपिटैलिटी डिपार्टमैंट की कंटीनें वगैरा के खर्चें आते हे जो इस डिमांड के अन्दर रखे गये है। पिछले हफते आदरणीय मुख्यमंत्री ने सदन में घोशणा की थी कि हरियाणा के मंत्री बचत की मरफ अपने कदम बढ़ा रहे है और एम0एल0एज0 फलैट में रहेंगे और टेलीफोन वगैरा की सहूलतें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारे सदन ने इस बात की प्र ांसाा की थी और कहा था कि यह बहुत अच्छा कदम है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) लेकिन अभी कल ही मुख्य मंत्री जी ने एक और घोशणा की कि जो बड़े मकान थोड़े किराये पर है उनको यूं का यूं रखा जाएगा। इस घोशणा से यह प्रतीत होता है कि मुख्य मंत्री तो ठीक है, वे अपनी घोशणा के मुताबिक एम0एल0एज0 होस्टल में चले गए लेनिक ऐसा नजर आता हैं कि बाकी पंद्रह के पंद्रह वजीर फलैटस में आने को तैयार नहीं है। (विघ्न)

चौधरी लाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। इसमें कोई भाक नहीं कि मुख्य मंत्री जी ने भारत में एक मिसाल कायम कर दी अपने त्याग, सच्चाई और ईमानदारी की लेकिन एक बात सोचने की है कि यदि मिनिस्टर्ज अपनी कोठियां छोड़ करके फलैटस में चले जाएंगे तो एम0एल0एज0 को आप कहां भेजेंगे? दूसरी बात यह है कि ऐसा करने से स्टेट को कोई बड़ी भारी मदद नहीं होगी बल्कि इसकी बदनामी होगी क्योंकि यहां वी0आई0पीज0 आते जाते रहते है। इसके अलावा इन कोठियों का हमें किराया भी कोई नहीं देना पड़ता।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार की नीयत यह नहीं थी कि मकान छोटे हों या बड़े हों बल्कि यह थी कि हरियाणा के लोग सरकार को चलाने के लिए जो करोड़ों रूपये का टैक्स देते है उसको बेरहमी से न खर्चा जाए। यही नहीं इसके पीछे यह नीयत भी थी कि जनता का जो लोग प्रतिनिधित्व करते है, जैसे एम0एल0एज0 हैं, मंत्री है और मुख्य मंत्री जी है, वे इस बात को सबसे ज्यादा महसूस करते है कि हरियाणा की गरीब जनता के पैसे का किसी किस्म का दुरूपयोग न हो। यह इसलिए भी किया गया था कि यह एक मिसाल बने उन अफसरों के लिए जो लाखों करोड़ों रूपया अपनी ऐ ाो–इ ारत पर बर्बाद करते हैं। यह इसलिए भी किया गया था ताकि लोगों में यह वि वास पैदा हो कि हरियाणा की जो सरकार है वह किसी तरफ भी गल्त तरीके से पैसा खर्च नही होने

देगी लेकिन वह उद्घोश आसमान में ही गूंज रहा था कि इन्होंने दूसरी घोशणा कर दी और ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने पहले फैसले से वापस कदमी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय वैसे तो यह सारा 28 लाख रूपये का खर्चा है जो कि सारे बजट का .05 प्रति ात ही बनता है लेकिन मतलब दरअसल यह नहीं होता। आज देखने की बात यह है कि 603 करोड़ रूपये के बजट का 45 प्रति ात भाग केवल तनख्वाहों में, पैट्रोल पर और दूसरे इस किस्म के खर्चों में प्रयोग होता है जिसका डिवैल्पमैंट से कोई संबंध नहीं। बजट का 270 करोड़ रूपया अगर इस किस्म के खर्चों में प्रयोग हो तो वैलफेयर की जो बात है, लोगों को सुविधाएं जुटाने की जो बात है, इसमें अड़चन आती है। (विघ्न)

वित्त मंत्री(श्री मूल चंद जैन): उपाध्यक्ष महोदय, इनसे यह पूछा जाए कि ये कौन सी डिमांड पर बोल रहे है?

चौधरी बीरेंद्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस डिमांड पर बोल रहा हूं जिसमें हरियाणा भवन का जिक है, एम0एल0एज होस्टल का जिक है और हौसपिटैलिटी डिपार्टमैंट का भी जिक है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा भवन में 34 सूटस है लेकिन 6 लाख रूपया गवर्नमैंट सबसिडी के तौर पर उसको देती है। यह बड़ी एनामली है क्योंकि कहा तो यह जाता है और यह बात अखबारों में भी आई है कि एम0एल0एज. और मिनिस्टर लोग वहां

ठहरते है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप सारे आंकड़ें लें वहां तो 90 परसैंट हरियाणा के अफसर रूकते है क्योंकि वे किसी न किसी बहाने से वहां का प्रोग्राम बना लेते है। ऐसे जो खर्चें है, उनको कम करने के लिए या उन पर रोक लगाने के लिये हरियाणा की जो केबिनेट है, हरियाणा का जो विधान–मंडल है उसको स्वयं एक मिसाल कायम करनी चाहिए, इसलिए वह फैसला किया गया था।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 5 पर अपने विचार रखूंगा। डिप्टी स्पीकर सहब, यह ठीक है कि ऐक्साइज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट हमारी वह एजैंसी है जिसके द्वारा करोड़ों रूपये हमारी गवर्नमैंट अपने खजाने में जमा करती है। इसके अलावा इस साल गवर्नमैंट की लाटरी की जो पालिसी थी वह नाकामयाब रही और मेरे आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा स्टेट को 15 करोड़ रूपये का घाटा पड़ा है। लेकिन इनके आंकड़ों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि 25 और 26 करोड़ रूपये तक इनकी आमदन पहुंच गई है जिसकी वजह से हरियाणा सरकार को 11 करोड़ यपये का मुनाफा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सेवा में दो बातें रखना चाहता हूं । यह ठीक है कि ठेके नीलाम करने से स्टेट को ज्यादा पैसा आया है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इस संबंध में मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अम्बाला के अन्दर 16 लाख रूपये का एक ठेका नीलाम हुआ। वह ठेकेदार 36,000 प्रूफ लीटर भाराब साल में उठाएगा। अगर इन

आंकड़ों के बारे में हम सोचें तो मतलब यह निकलता है कि दो सौ बोतल वह एक दिन में बेचेगा और एक बोतल की कीमत 26 रूपये पड़ेगी। (विघ्न)

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी भोर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, ये कौन से ठेके की बात कर रहे है?

चौधरी बीरेंद्र सिंहः मैं अम्बाला के डी0सी0 रोड के ठेके की बात कर रहा हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर 26 रूपये में उसे भाराब की बोतल पड़ेगी तो वह कैसे 18 रूपये में बेचेगा? आठ रूपये के घाटे को वह कहां से पूरा करेगा? मैं तो समझता हूं कि इस घाटे को पूरा करने के लिए वह गलत भाराब बनाएगा और बेचेगा क्योंकि गलत भाराब की कास्ट उसको दो तीन रूपये पड़ती है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय यह बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सरकार ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। एक तरफ तो इन्होंने भाराब के उठानरे में 40 परसैंट की कटौती की है लेकिन दूसरी तरफ ठेके की बोली इतनी ज्यादा गई कि सरकार को यह आंकड़े नजर नहीं आएं कि जो आदमी 26 यपये की बोतल खरीदेगा वह उसे 18 यपये की कैसे बेचेगा और वह इस घाटे को कैसे पूरा करेंगा? इससे तो डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में इलीसिट डिस्टिले ान होगी और वह आदमी करोड़ों रूपये कमाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक्साइज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट के जो कानून है, जो रूल्ज है वे ऐसे है कि देहात में अगर दो बोतल भाराब भी कहीं से

निकलती पकड़ी जाए तो संबंधित व्यक्ति को 6 महीने के लिए जेल में जाना पड़ता है और पुलिस उसके ऊपर ऐक ान लेती है लेकिन भाहर के अन्दर अगर ऐसा हो तो उस पर पुलिस उसके ऊपर ऐक ान लेती है लेकिन भाहर के अन्दर अगर अगर किसी की इलीसिट डिस्टिले ान की भटिठयां भी पकड़ी जाएं तो उसके ऊपर डिपार्टमैंट कार्यवाही करता है। मुझे कैथल का एक केस याद है। छः महीने पहले वहां एक डिस्टलरी पकड़ी गई। जब भाोर किया गया कि उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करो तो कहा गया कि यह डिपार्टमैंट की औप ान है या तो वह पुलिस केस बनवा ले या खुद डील कर ले। खुद इन्होंने क्या किया? पांच हजार रूपये की पैनल्टी लगा कर खु ा हो गए।

श्री उपाध्यक्षः आप दो मिनट में वाइंड अप कर लीजिए।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः तो मैं एक्साइज एंड टैक्से ान मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना करूंगा कि वे कानून में ऐसा प्रावधान करें जिससे ठेकेदारों द्वारा किए जाने वाले इलीसिट डिस्टिले ान के केसिज को सीधे पुलिस के हवाले किया जा सके और जैसा हम रोज अखबारों में पढ़ते है कि नकली भाराब पीने से बिहार में या बम्बई में सैकड़ों आदमी मर गए इस तरह की घटनाएं हरियाणा में न हो। क्योंकि ऐसी भाराब से सैंकड़ों आदमी बम्बई में मरे हैं इसलिए हरियाणा में ऐसी दुकानें न हों।

दूसरी बात मैं सेल्ज टैक्स के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । अभी पिछले दिनों मंत्री महोदय ने यहां हाउस में जवाब दिया कि यमुनानगर में ऐक्साइज और टैक्से ान के अधिकारियौं ने किसी बिजनैस प्रिमिसिज पर रेड किया था तो उन लोगों को पीटा गया। उन अधिकारियों ने पुलिस में केसिज दर्ज करवाये थे लेकिन वे बिजनैसमैंन किसी खास आदमी से ताल्लुक रखने वाले थे, भााखाओं में जाने वाले थे इसलिए उनके केसिज साबका गृह मंत्री जी ने विदड्रा करवा दिए। अगर इस तरह से केसिज को विद्रडा किया जाता है तो सारे के सारे अधिकारियों में डिमोरेलाइजे ान आयेगी। वे जिस नेक–नीयत से काम करना चाहते है, नहीं कर पायेंगे। सेल्ज टैक्स के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका बहुत ज्यादा इवेजन होता है। अगर सरकार कड़े तरीके अपना कर इसको वसूल करे तो जहां 171 करोड़ रूपये एक्साइज एंड टैक्से ान से जाता है उससे भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। एक ई0टी0ओ0 असैसमैंट करता है, अगर वह गलत करता है तो उसके खिलाफ बिजनैस मैन अपील कर सकता है लेकिन सेल्ज टैक्स में बहुत बड़ें फला हैं (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आपका समय हो गया। श्री फतेहचंद जी आप बोलें।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः मैं सिर्फ एक मिनट लेना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप रिपीट कर रहे है।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय मुझे आप पूरी बात करने का मौका तो दें।

श्री उपाध्यक्षः मैंने श्री फतेह चंद विज को बोलने के लिए कह दिया। अब आप बैठिए (विघ्न)

चौधरी बीरेंद्र सिंहः मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिए।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः मुझे आप वाइंड–अप करने का तो मौका दें।

श्री उपाध्यक्षः आपको एक मिनट और दे रहा हूं।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः बहुत अच्छा जी।

विकास मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस की सैंस ले कर हर मैम्बर का टाईम मुकर्रर किया हुआ है। इन्होंने डबल टाईम तो पहले ही ले लिया है।

Mr. Deputy Speker: He will now wind up in one minute.

चौधरी बीरेंद्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय मैं सेल्ज टैक्स और ऐक्साइज की बात इसलिए कर रहा था कि इस बारे में कुछ सुझाव भी हाउस के सामने रखना चाहता हूं। मैं कोई नुक्ताचीनी

की गर्ज से ही नहीं खड़ा हुआ हूं। मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान जाना चाहिए कि हजारो की तादाद में मैटाडोर गाडिया हरियाणा में किराये के रूप में चल रही है। उनके रोहतक में बाकायदा अड्डे बने हुए है। वे सवारियों को लेकर जाती है लेकिन उनसे कोई पैसेंजर टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है। इसलिए उन पर टैक्स लगना चाहिए। जो अपने आपको जनता पार्टी के एक्टिव वर्कर कहते है वे लाखों रूपया कमा रहे है। इसलिए मैं मंत्री महोदय के नोटिस में ला रहा हूं कि अगर उन सोर्सिज को टेप किया जाये तो सरकार को लाखों रूपए की आमदनी हो सकती है। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्षः अब पोहलू साहब बोलेंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू(पाई): डिप्टी स्पीकर साहब.....

कंवर राम पाल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राव बीरेंद्र सिंह जी की सीट से आज पोहलू साहब कैसे बोल रहे है? क्या यह सीट उनको दे दी गई है?

श्री उपाध्यक्षः उनका माईक खराब है, इसलिए वह यहां से बोल रहे है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी बहुत–बहुत मेहरबानी, आपने मुझे समय दिया। मैं डिमांड नम्बर चार जो रेवेन्यू के बारे में है और डिमांड नम्बर आठ जो रोडज के बारे मैं है इन पर बोलना चाहता हूं। कुछ थोड़ा सा डिमांड नम्बर एक जो विधान सभा के बारे में है उस पर भी अर्ज करना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जब से जनता सरकार वजूद में आई है तब से हम बड़ी उम्मीदें लगाये बैठे थे कि कांग्रेस ने जो गलतियां की है उन्हें वे नहीं करेगें। हमारे पुराने सियासी लीडर चौधरी देवी लाल जी आज चीफ मिनिस्टर है हमैं ख्याल था कि इनके होते जनता का बहुत भला होगा, गरीब किसानों का भला होने की भी उम्मीद दिखाई देती थी लेकिन भला नहीं हुआ। इसकी मिसाल मैं देता हूं कि आज तकरीबन एक महीना **(11.00बजे)** पहले गुड़ का भाव 25 रूपये मन से कम था (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, उस समय चीनी का भाव अढ़ाई रूपये किलो का खुले बाजार में था। अब की जो हालत है, वह आप भी सुन लो।.....(व्यवधान)..... डिमांड नं0 4 में यह बात आती है। डिप्टी स्पीकर साहब, किसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह रही है कि मेनत तो वह करता है और उसका फायदा दूसरे उठाते है। किसान इस दे ा की फौज में भर्ती होकर दे ा को बाहरी हमलों से भी बचाता है। चीन को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया था कान्ति देसाई या सुरे ा न नहीं दिया था। आज किसान के ऊपर डिवाईड एंड रूल की पालिसी लागू करके दबाया जा रहा है। उसे चार हिस्से में बांटा गया है। छः एकड़ तक

वाले का मालिया माफ। दस एकड़ से बारह एकड़ तक लैंड टैक्स बढ़ाया गया है और उससे बेचारे किसान को मार दिया है। यह क्यों किया गया है? यह इसलिए किया गया है ताकि किसानों की रैली में जो एकता दिखाई दी है, उसे तोड़ा जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर चार करोड़ रूपया जो किसानों पर टैक्स का लगाया गया है इसे कारखनेदारों पर लगाते, भारमायेदारों पर लगाते तो उससे किसानों का कुछ भला होता। लेकिन हमारे फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने यह बात समझ ली है कि किसानों की एकता को तोड़नें के लिये यह जरूरी है कि इनको रगड़ो। इनकी पब्लिक स्टेटमैंट है कि जब हम सारी सुविधाएं देहात वालों को देने जा रहे है तो क्या न देहात पर भी टैक्स लगाए जायें। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इनकी इसी बात को लें तो ये इन्ही का जूता इन्हीं का सिर वाली बात सिद्ध कर रहे है। गरीब और अमीर का फर्क फिर कैसे कम होगा? सिर्फ गरीब के लिए यह बजट है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अफसोस की बात है कि देहात और भाहर का सवाल यहां पर पैदा हो रहा है जोकि नहीं होना चाहिए था। उलटा उनके ऊपर टैक्स लगाते चल जायें, यह कोई उचित बात नहीं। सब एम0एल0एज0 साहेबान को इन गरीब भाईयों का भला करना चाहिए। आज किसान के ऊपर इतने टैक्स है कि वह मुकम्मल तौर पर उनके बोझ से दब चुका है और वह मजबूर होकर बगावत भी कर सकता है। जब किसान एमरजैंसी के दौरान नहीं दबे तो अब तो दबने का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना

चाहता हूं कि किसान को और तबाही से बचने के लिए उसके ऊपर टैक्सों का और बोझ न लादा जाये। जो चीजें उसे खरीदनी पड़ती है, वे उसको सस्ते भाव पर मुहैया की जाये और जो उसकी पैदावार हे उसकी उसे उचित कीमत दिलवायी जाये।..... (व्यवधान)..... आज गुड़ का भाव 55 रूपये मन हो गया है। इसलिए इस पर भी कंट्रोल किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नं0 8 बिल्डिंगज एंड रोडज की है जोकि 38 करोड़ रूपये से कुछ ज्यादा की है। यह पैसा काफी ज्यादा है। सड़कों के बारे में हम सब को पता है कि अगर 38 करोड़ रूपया हम मंजूर करेंगे तो मुि कल से 19 करोड़ रूपया वहां तक पहुंचेगा। इस सिस्टम को हमैं बदल देना चाहिए। मेरी राय यह है कि आप वजीर चाहे जितने मर्जी बनाओ, बे ाक हरेक डिपार्टमैंट के लिए एक अलग मिनिस्टर बना लो, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो महकमैं के सारे काम को मौके पर जाकर चैक करे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपके इस महकमें में बहुत से अफसर ऐसे है जो सरकार को फेल करना चाहते है। मैं यह चाहता हूं कि जो आपके यहां गलत अफसर भर्ती हुए है, उनको बे ाक आप निकाल दें लकिन काम ठीक तरीके से चलना चाहिए। यह जो ठेकेदारी का सिस्टम है, इसको भी बंद किया जायें। ठेकेदारों से जब तक डिपार्टमैंट वालों को हिस्सा नहीं मिलता तब तक कोई काम नहीं होता। उनके जो परसैंटैज दी जाती है उसकी वजह से आज इस महकमें के लोगों को इतनी

आमदनी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसके बावजूद भी आप कहते है कि इस बजट को हम पास कर दें। पी.डब्ल्यू.डी. के महकमें के जितने लोग है, उनकी आमदनी क्या है उनकी प्रापर्टी क्या है, उनकी अगर जायज आमदनी का हिसाब लगाकर देखा जाये तो उससे कहीं ज्यादा निकलेगी। उनकी जा फालतू आमदनी है, अगर वह जब्त करके गरीबों को दे दी जाए तो इससे बहुत से लोगों का भला हो सकता है। एक बात इक्वैलिटी आफ ला की यहां पर कही जाती है। जमींदार की जमीन की तो हद 18 एकड़ रख दी गई है जिससे आम किसान पिट गया है जबकि कारखानेदार, सरमायेंदार, और भाहरी इंडस्ट्रियलिस्टस की 90,000 रूपये से भी ज्यादा की है। इसलिए इस रकम से ऊपर की इनकी जितनी जायदाद है, वह सब सरकार गरीबों में बांट दे क्योंकि एक एकड़ जमीन की कीमत लगभग 5,000 रूपये हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो गरीब बच्चों को सड़क पर रोड़ी कूटने या कोई और काम करने के लिए अपने मां बाप के साथ जाना पड़ता है, उनकों वहां पर नहीं जाना पड़ेगा। उन नाबालिग लड़कियों को जिन्हें दिहाड़ी करके अपना पेट पालना पड़ता है, उनकों भी सड़क पर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आम जनता को इससे कोई एतराज नहीं हैं। सरकार जब तक अर्बन लैंड पर सीलिंग नहीं लगाती तब तक जनता का कोई भला होने वाला नहीं है।.....

.....

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस सरमायेदार को बदलो और ज्यादा नहीं तो कम से कम ठाकुर बीर सिंह जी को फाईनैंस मिनिस्टर बनाया जाए। जय हिन्द।

श्री मनी रमा(डबवाली–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डिमांड नं0 13 और 4 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मांग संख्या 13 के सन्दर्भ में मैं अपनी जनता सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस ने जो विद्यार्थियों को वजीफा पहले 8 रूपये महीना मिलता था, उसे बढ़ाकर 16 रूपये कर दिया है। यह बड़ी सराहना की बात है। यह जो वजीफा हरिजनों और बैकवर्ड विद्यार्थियों को ही मिलता है, यदि इसे दूसरी जातियों के गरीब बच्चों के लिये भी कर दिया जाये तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। इसके अलावा यह जो 8 रूपये से बढ़ाकर 16 रूपये वजीफा किया गया है, अगर इसे पहली जमात से सातवीं जमात तक के बच्चों के लिये भी दिया जाये तो अच्छी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली सरकार के वक्त में ओल्ड ऐज पैं ान 25 रूपए दी जाती थी लेकिन हमारी जनता सरकार ने इसको पच्चीस से बढ़ाकर पचास रूपया कर दिया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी हमारे देहात में ऐसे लोग है जो बहुत बूढ़े है और जिनका कोई सहारा नहीं है, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसे बेसहारा लोगों को जल्दी से जल्दी पैं ान दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 13 के बारे में थोड़ा सा और कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने हर गांव में हरिजन चौपाल बनाने का फैसला किया है यह बहुत ही अच्छा फैसला है और बड़ा सराहनीय कदम है। हरियाणा प्रान्त भारतवर्श में पहला प्रांत है, जहां इस प्रकार की स्कीम आरम्भ की गई है। पहले जब हरिजन लोगों के कोई बारात आती थी तो ज्यादा मेहमान आ जाते थे तो उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे पूरी आ ाा है कि आने वाले समय में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पर हरिजन चौपाल नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 4 के बारे में कहना चाहता हूं जो रेवेन्यू के बारे में है। पहले सरकार ने सवा छः एकड़ तक मालिया बिल्कुल माफ किया था और यह सरकार का बहुत अच्छा कदम था। इसके अलावा इस बजट में सवा छः एकड़ से ज्यादा जमीन के लैंड होल्डिंग्ज टैक्स पर जो 33 परसेंट सरचार्ज लगाया था सरकार ने उसको भी वापिस ले लिया है, यह भी बहुत ही अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है। इससे छोटे किसानों को काफी राहत मिलेगी। मैं अपने वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

श्री मूल चंद मंगला(पलवल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सब से पहले डिमांड नम्बर पांच

पर बोलना चाहता हूं जो कि ऐक्साइज एंड टैक्से ान के बारे में है। बाबू मूल चंद जी जब मिनिस्टर नहीं थे तो कहा करते थे कि हमने जनता से वायदा किया था कि हम अगर सत्ता में आ गए तो सेल्ज टैक्स को खत्म कर देंगे। मैं यह जानता हूं कि कोई भी सरकार बगैर टैक्स के नहीं चल सकती है। मैं सैल्ज टैक्स के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं जिससे कि इसको खत्म किया जा सकता है। हमारी स्टेट की सेल्ज टैक्स से आमदनी साठ करोड़ है और जैसा कि सैंटर कहता है कि अगर कोई स्टेट सेल्ज टैक्स खत्म करती है तो हम उस स्टेट का आधा घंटा पूरा करेंगे। इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, तीस करोड़ रूपया सेंटर से मिल जाएगा। तीस करोड़ रूपया बाकी बचता है। इसको पूरा करने के लिए सरकार को चाहिए कि सेल्ज टैक्स की बजायें यहां पर कोई चीज बनती है, मैनुफेकचर होती है वहां पर पैंतीस करोड़ की एक्साइज ड्यूटी लगा दें। इससे हमारी आमदनी पांच करोड़ और बढ़ जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आमतौर पर यह महसूस किया जाता है कि बिजनैसमैन बेईमान है। ऐसा करने से लोगों की यह ि ाकायत भी दूर हो जाएगी और बिजनैस कम्युनिटी को हिसाब किताब रखने में जो आजकल परे ाानी होती है वह भी खत्म हो जाएगी और हमारी स्टेट की आमदनी भी बढ़ जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हलवाइयों पर जो टैक्स लगाया है या टैक्स लगाने की जो नीति बनाई है, मैं समझता हूं कि सरकार को इससे आमदनी बहुत कम होगी और भाोर ज्यादा मचेगा और

हलवाइयों को भी ज्यादा परे ाानी होगी। उपाध्यक्ष महोदय ज्यादातर हलवाई अनपढ़ होते है, अगर उनके ऊपर टैक्स लगता है तो उनको काफी परे ाानी होगी और वे कोई हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे। मैं चाहूंगा कि हलवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। इससे कोई वि ोश फायदा होने वाला नहीं है और ऐसा करने से ऐजीटे ान होने का भी डर है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर 8 जो बिल्डिंग एंड रोडज के बारे में है, की बाबत कहना चाहता हूं। हरियाणा में बारह तेरह सड़कें ऐसी हैं जो पंचायतों की है और उन्हें गवर्नमैंट ने अपने कब्जे में नहीं लिया है। उनकी हालत काफी खराब है और उन पर चलना भी काफी मु कल है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार उनको अपने कब्जें में ले ताकि लोगों को सुविधा मिल सकें। हमारे यहां एक कारना गावं है। मुख्य मंत्री महोदय वहां गए थे और उस सड़क को उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा था कि इस सड़क पर लोग कैसे चलते होंगे। सारी सड़क पंचायत की है। मुख्य मंत्री महोदय ने वि वास दिलाया था कि इस सड़क को सरकार ले लेगी और कोि ा ा करेगी की इसकी मुरम्मत जल्दी की जाए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हमारे प्रान्त में जितनी भी पंचायत की सड़कें है और जिनकी हालत खराब है उनको सरकार ले ले और उनकी मुरम्मत कराए ताकि आम जनता को और किसानों को लाभ हो। कई

दफा देखा गया है कि जब किसान अपनी बैल गाड़ी लाते है तो उनको ऐसी सड़कों की वजह से काफी नुक्सान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0 11 अर्बन डिवैल्पमैंट से संबंधित है। अर्बन डिवैल्पमैंट के लिए सरकार ने जो खर्चा रखा है उसका बंटवारा ठीक तरीके से नहीं किया गया हैं। यह देखा गया है कि कुछ मयुनिस्पिल कमेटीज को तो बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है और म्युनिसिपल कमेटीज को बहुत कम पैसा दिया गया है। जिन म्युनिसिपल कमेटीज की आमदनी सैंकड़ों लाख रूपए है उन्हीं को बजट में ज्यादा पैसा दिया गया है और जिनकी आमदनी पंद्रह बीस लाख रूपया है उनको कम पैसा दिया गया है। मेरी सरकार से प्रार्थना है जिन म्युनिस्पिल कमेटीज की आमदनी कम है उनको ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। जिस कैटेगरी में जिस म्युनिसिपल कमेटी को रखा गया है उसको उसी रे ाो में पैसा मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पलवल म्युनिस्पिल कमेटी की बाबत बताना चाहता हूं। वहां पर सिवरेज का काम चल रहा है लेकिन केवल 1.10 हिस्से में चल रहा है। इसका मतलब यह है कि जहां पर बड़े लोग रहते है, अफसर रहते है वहां पर यह सिस्टम लागू नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि सरकार वहां पर अधिक पैसा दे ताकि सारे भाहर में सिवरेज सिस्टम चालू हो सके। वैसे तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सभी भाहरों में सिवरेज सिस्टम चालू होना चाहिए लेकिन जहां पर सिवरेज सिस्टम के लिए काम किया जा रहा है वहां पर सरकार को अधिक

पैसा देना चाहिए। ताकि वहां पूरे भाहर की डिवैल्पमैंट हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं फौरेस्ट डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं । जितना पैसा इस विभाग को दिया गया है, इस पर इससे भी ज्यादा खर्चा होना चाहिए। यह ठीक है कि पहले से पैसा ज्यादा रखा गया है लेकिन मेरी सरकार से प्रार्थना है कि और अधिक पैसा इस विभाग को दिया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि फौरेस्ट विभाग को फलदार वृक्ष लगाने चाहियें। इससे दो फायदे होंगे एक तो बीमारी कम होगी और दूसरे लोगों को खाने के लिए फल मिल सकेंगे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह फौरेस्ट डिपार्टमैंट को आदे ा दे कि वह कम से कम पचास परसैंट फलदार वृक्ष लगाए और पचास परसैंट दूसरे वृक्ष लगाए। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कहकर मैं समाप्त करता हूं।

चौधरी हरि चंद हुड्डा(किलोई): डिप्टी स्पीकर साहब, बजट के बारे में जो ये धारा एक से लेकर पच्चीस तक है, इनके बारे में मैं अपने रिस्पैक्टेबल मैम्बर्ज और आफिसर्ज को यह बताना चाहता हूं कि इसका ओरिजन क्या है (व्यवधान)। मैं डिमांड नम्बर चार पर बोलना चाहता हूं कि यह जो धारा हमारे सामने आई है या जो बजट हमारे सामने आया है दरअसल यह डैमोक्रेसी पैदा करता है, सो ालिजम पैदा करता है और पूंजीवाद पैदा करता है, डिक्टेटरि ाप पैदा करता है। अगर घर के बजट का हमारी मां बंटवारा करती है तो डैमोक्रेसी पैदा होती है और इसी बजट का उसी घर में हमारी चाची बंटवारा करती है तो

सो ालिजम पैदा होता है। अगर उसी घर के बजट का हमारी मौसी बंटवारा करती है तो पूंजीवाद और डिक्टेटरि ाप पैदा होती है।

डिप्टी स्पीकर महोदय, 30 साल से इस दे ा के अन्दर पूंजीवाद और मौसीवाद की हकूमत चल रही थी। आज जो बजट आया है उसमें एक से लेकर पच्चीस तक जो मदें है, उनमें जो बंटवारा दिखाया गया है, वह सही डैमोक्रेसी का, सही मां का बंटवारा दिखाई पड़ता है.....(ाोर)

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आप तो इस मसले पर किताब लिख सकते हो।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बजट है, इस बजट को देहात में.....(ाोर)

श्रमती सुशमा स्वराजः उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दे ा में चाचा और मौसा तो बंटवारा कर सकते है, लेकिन चाची और मौसी नहीं करती। इसलिए इन्होंने पता नहीं कहां से यह ओरिजन बताया है। हमारे दे ा में कभी चाची या मौसी बंटवारा नहीं करतीं।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, जितना भी बंटवारा यहां हमारे दे ा में किया गया है, वह लक्ष्मी ने ही किया है यानी आदमी कभी भी बंटवारा करने वाला नहीं हुआ। यह जो बजट यहां पर पे ा किया गया है, अगर यह अस्सी

फीसदी किसानों और मजदूरों का भला नहीं करता तो हम सभी इस पर यह कह देंगे कि आज जो सरकार की मां वाद की पालिसी है, उसको हम नहीं चलने देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थ भाास्त्र नहीं सीख रहा हूं.....
.....(ाोर)

आवाजें: उपाध्यक्ष महोदय, समय का भी ध्यान रखा जाए।

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आपका समय हो गया है आप बंद करिए।

चौधरी हरि चंद हुड्डाः डिप्टी स्पीकर साहब, सिर्फ एक दो बातें और कह कर मैं समाप्त करूंगा। जो लोग आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तीस सालों से अर्थ भाास्त्र सीख कर यहां पर आए है वे थ्यूरी पर ही रहे है और उसको कोई फायदा नहीं रहा। आप को पता है कि जो देहात का आदमी होता है वह प्रैक्टीकल काम करता है और वह बिना कुछ सीखे कामयाबी हासिल करता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि थ्यूरी की बजाए आदमी को प्रैक्टीकल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए तभी इस दे ा का ज्यादा उत्थान हो सकता है.....(ाोर एवं व्यवधान)

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्र न है कि भाई हुड्डा साहब भाई, मौसी, चाचा और चाचीवाद पर बोल रहे है या कि बजट की किसी मद पर बोल रहे है? (ाोर)

श्री उपाध्यक्ष: स्वामी जी आप बैठिए, हुड्डा साहब खत्म करने जा रहे है, इनका समय खत्म हो गया है..... (ाोर).....

चौधरी हरि चंद हुड्डा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं स्वामी जी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने गलत बात कही। मैं सही बात पर ही बोल रहा हूं। मैंने काम करके खाया है न कि मुफ्त में बैठ कर खाया है (ाोर)। मैं अपनी सरकार को और अपने अफसरों को निवेदन करूंगा कि जो बजट प्रोपोजल्ज है, उनको सही ढ़ंग से इम्पलीमैंट किया जाए। इस बजट में जो कुछ रखा गया है, मैं उसकी कामयाबी की प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार इसको सिरे चढ़ाएगी। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी नारायण सिंह(पटौदी–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। सबसे पहले मैं डिमांड नम्बर आठ जो कि सड़कों के संबंध मैं है, उस पर बोलना चाहता हूं। हमारे पटौदी

हलकें में बहुत सारी सड़कें ऐसी है जिनका बनाया जाना बड़ा ही आव यक है। मुझे पूर्ण आ ाा है कि संबंधित मंत्री महोदय मेरी इस प्रार्थना पर अव य ही ध्यान देंगे। सब से पहली रोड है घानी महचाना। इसको पटौदी और हेली मंडी को जाने वाली सड़क से मिलाया जाना चाहिए, यह कोइ दो अढ़ाई फर्लांग का फासला हैं। दूसरी सड़क है मुबारिकपुर से मूंडा खेड़ा। तीसरी फारूखनगर से चांद डानी, यहां पर एक हरिजनों की बस्ती है। इससे आगे है फारूखनगर से फाजलपुर। एक सड़क है गुगाना से पटौदी। फारूखनगर से हेली मंडी को जाने वाली रोड केवल आधा फर्लांग के लगभग है। इसमें कई मोड़ भी आते है और यह सड़क हरिजनों के घरों से होकर जाती है। इसको अगर सीधा किया जाए तो हरिजनों को इससे बहुत लाभ होगा और लोग एक्सीडेंट से भी बचेंगे। मुझे पूर्ण आ ाा है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नम्बर तेरह के बारे में बोलना चाहता हूं। इसके तहत हरिजनों को जो मकान बनााने के लिए ग्रांट दी जाती है वह बहुत थोड़ी है, अतः मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि जो दो हजार रूपए के लगभग ग्रांट की रा ि ा है उसको बढ़ा कर तीन हजार रूपए तक कर दिया जाए ताकि गरीब हरिजनों को और दूसरे गरीबों को कुछ राहत मिल सके। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेने

से पहले एक बार फिर सरकार से कहूंगा कि जो–जो बातें यहां पर कहीं गई है, उनकी तरफ खास तवज्जहो दी जाए।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): उपाध्यक्ष महोदय, आज 13 विभिन्न विभागों की मांगे, जो कि इस सदन के सामने रखी गई है, उन पर चर्चा चल रही है। मैं समय के अभाव को देखती हुई उनमें से मांग नम्बर 1, 5, 14 तक ही अपनी बात को सीमित रखना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मांग नम्बर एक को लेकर अपने विचार रखूंगी जिसमें 34,74,000 रूपया विधान सभा के लिए मांगा गया है। .... जब हमारे वित्त मंत्री महोदय अपना बजट भाशण पढ़ रहे थे तो मुझे दु:ख हुआ यह देखकर कि उसमें एक पूरा पन्ना सर्विसिज की भलाई के लिए था। उसमें कहीं पर तो वर्क चार्ज्ड एम्पलाईज के वेतनमानों का जिक्र है और कहीं पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरर्ज के वेतनमानों का जिक्र है लेकिन न मालूम हमारे वित्त मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात क्यों नहीं आई कि इस बजट में.....

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग नम्बर पाचं पर अपने विचार रखना चाहूंगी। जब मैं वित मंत्री महोदय का बजट भाशण पढ़ रही थी, तो एक हैरानगी की बात मेरे सामने आई। उसमें यह लिखा था कि 40 हजार से व्यापारियों का टैक्सेबल क्वांटम एक लाख कर देने से और मैनुफैक्चरर्ज का दस हजार बढ़ा कर पच्चीस हजार कर देने से सरकार को चौदह लाख रूपए की बिक्री

कर की हानि होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ नहीं आता कि वित मंत्री महोदय ने किस आधार पर ये आंकड़े आंके है। मेरी जानकारी के अनुसार यह क्वांटम एक लाख की बजाए चाहे कितना भी क्यों न बढ़ा दें, इससे सरकार को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होने वाली है। मैं आपको बताती हूं कि कैसे इस तरह का नियम बना हुआ हैं जिसके तहत कोई भी व्यापारी जो पहले चालीस हजार की सलाना सेल करता था और वह व्यापारी जो चाहे सौ रूपए का भी दूसरी स्टेट से माल मंगवाता था या सौ रूपए का भी माल निर्यात करता था तो उसे कंपलसरी रूप से रजिस्टर होना पड़ता थो, अनिवार्य रूप से उसको पंजीकृत होना पड़ता था। रजिस्ट्रे ान के बाद उसको एक रजिस्ट्रे ान सर्टीफिकेट भी मिल जाता था जिसको आर0सी0 कहते है। उसका यह फायदा होता था कि जब कोई व्यापारी किसी से कोई माल लेना चाहता था तो वह उसका सेल्ज टैक्स नहीं देता था। वह केवल आर0 सी0 दिखा देता था कि मैं रजिस्टर्ड डीलर हूं। अगर वह खुद माल बेचता था तो उस पर वह कंज्यूमर से सेल्ज टैक्स लेता था। तो उपाध्यक्ष महोदय, फर्क केवल ऐजंसी का पड़ा है कि चालीस हजार वाला व्यापारी अब रजिस्टर नहीं हो सकता और केवल एक लाख वाला ही रजिस्टर होगा। इसलिए चालीस हजार वाले व्यापारी को अब आर0सी0 नहीं मिलेगा और जब वह सामान खरीदने के लिए जाएगा तो उसको वहां पर सेल्ज टैक्स देकर आना पड़ेगा। फर्क केवल एजेंसी का है। पहले जो चालीस हजार तक ही सेल करता था वह सरकार को सेल्ज टैक्स देता था

और अब सरकार को कर वह देगा जो एक लाख के करीब की सेल करता है। मतलब यह कि जो छोटे व्यापारी को हैरास्मैंट होती थी, वह इससे बच गया है। इसलिए यह चौदह लाख के घाटे को देखकर कई बार सदस्यों को यह महसूस होता है कि न मालूम व्यापारियों को कितना बड़ा कंसै ान दे दिया गया है। वैसे देखा जाए तो इस में कीं पर भी किसी तरह का कंसै ान नहीं दिया गया है बल्कि इससे जो छोटे व्यापारियों को दिक्कतें थी, वे खत्म हो गई है। कर की वजह से सरकार को कोई हानि नहीं हुई है, ऐसी मेरी धारणा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात हमारे वित मंत्री महोदय ने कही थी और अपने बजट भाशण में यह इ ाारा भी दिया था कि फरीदाबाद, सोनीपत, मतलब कि दिलली के आस–पास के इलाकों में जो माल बनता है, उसकों बिना सेल्ज टैक्स दिये लोग बाहर ले जाते है क्योंकि इन लोगों ने इपने कार्यालय बाहर रखे हुये है। इसलिए इनके ऊपर कोई नया कर लगाने का प्रावधान करना है। उपाध्क्ष महोदय, कानून की नजर से जब मैं उसको देखती हूं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कर लगाना अकेले राज्य सरकार के लिये संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा कर लगाने की इच्छा प्रकट करेंगे तो नि चत रूप से उस की अनुमति राश्ट्रपति महोदय से लेनी होगी। यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि करोड़ों रूपये की इससे सरकार को हानि हो रही है। जिन लोगों ने अपने कार्यालय बाहर खोल रखे है, वे माल भर कर बाहर ले जाते है।

इसके लिये मैं एक सुझाव वित मंत्री महोदय को देना चाहती हूं कि सैंट्रल सेल्ज टैक्स में एक अमैंडमैंट की आव यकता है। सैंट्रल सेल्ज टैक्स में एक प्रावधान है कि अगर एक स्टेट की कोई फैक्टरी दूसरी स्टेट में स्थित अपने ही कार्यालय को, अपना माल भेजती है तो वह माल ट्रांसफर की डैफीने ान में आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसको सीधा बनाने का तरीका यह है कि हमारे मुख्य मंत्री जी तथा वित मंत्री जी दोनों केंद्रीय सरकार के वित मंत्री चौधरी चरण सिंह से जा कर मिलें और बतायें कि इससे हमारी सरकार को बहुत ज्यादा हानि हो रही है। इसके अलावा जो बाकी स्टेटस है उनमें भी इस तरह की हानि हो रही है। ऐसा करने से इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। या तो वे इस तरह के माल को भेजने में ट्रांसफर से हटा कर सेल की डैफिनि ान में ले आएं या दूसरी चीज वह यह करें कि इस ट्रांसफर पर भी सेल्ज टैकस लगा दिया जाये। अगर इसको ट्रांसफर की ही डैफिने ान में रखा जाता है तो यह कहें कि जितना सेल्ज टैक्स लगता है वह ट्रांसफर गुडज पर भी लगे। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहती हूं कि फरीदाबाद में दो सौ करोड़ रूपये की प्रोडक ान होती है अगर हम यह मान लें कि वहां के आधे लोग टैक्स देते है तो भी सरकार को सौ करोड़ रूप्ये की प्रोडक ान पर टैक्स के रूप में आमदनी होगी। अभी भाई मंगला जी ने सेल्ज टैक्स को एबालि ा करने की बात कही

थी। उपाध्यक्ष महोदय वास्तव में पोजी ान यह है कि सेल्ज टैक्स को एबालि ाा करने की बात नहीं है बल्कि इसको एक्साइज डियूटी में मर्ज करने की बात है। पूरी हिन्दुस्तान में 26 सौ करोड़ रूपया सेल्ज टैक्स से आता है और पांच हजार करोड़ रूपया एक्साइज डियूटी से आता है इसलिये जहां जहां कितनी एक्साइज डियूटी लगी हुई है उसको पचास प्रति ात बढ़ा दयिा जाये और सेल्ज टैक्स को एबालि ा कर दिया जाये। इससे तीन लाभ होंगे। जैसे हरियाणा सरकार को 88 करोड़ रूपया सेल्ज टैक्स से मिलता है तो यह सरकार केंद्रीय सरकार से गुजारि ा करे कि आप पचास प्रति ात एक्साइज डियूटी बढ़ा दीजिये और आज जितनी इंकम हमें सेल्ज टैक्स से होती है उतनी हमें दे दीजिये और अगले साल दस प्रति ात वृद्धि कर दीजिये.....

श्री उपाध्यक्षः सुशमा जी आपका समय हो चुका है, आप त ारीफ रखें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः उपध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी मसला है इसलिये मैं दो मिनट और लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः आपकी बात बाबू जी समझ गये है, आप त ारीफ रखें।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अगर आपका यही आदे ा है तो मैं इतना ही कह कर अपना स्थान लेती हूं। धन्यवाद।

चौधरी देसराज(इंदरी): डिप्टी स्पीकर साहब, सब से पहले मैं डिमांड नं 4 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह डिमांड रैवेन्यू से ताल्लुक रखती है और इसमें दिक्कत यह है कि आम किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मुजारा हो या पट्टेदार हो उसको पटवारी के पास खसरा और गिरदावरी की नकल लेने के लिये जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि जैसे जमाबंदी की नकल तहसील में होती है उसी तरह से खसरा और गिरदावरी की नकल भी तहसील में जानी चाहिये। ऐसा करने से किसानों का बहुत टाईम बचेगा। इसके अलावा पटवारी के पास भी काम बहुत ज्यादा है इसलिये छोटे हल्के बनाये जाऐ ताकि पटवारी पूरी हल्के का काम अच्छी तरह से कर सकें। अगर ऐसा किया जाता है तो पटवारी भी अपना काम अच्छी तरह से कर सकेगा और जनता को भी इससे लाभ होगा। इसके बाद मैं डिमांड नं पांच पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि प्रोहिब ान पालिसी बहुत अच्छी है।

चौधरी लाल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कि लोग इसलिये परे ाान है कि पटवारी पटवारखाने में नहीं रहता बल्कि वह भाहर में रहता है।

चौधरी देसराज: मैं कह रहा था कि प्रोहिब ान पालिसी अच्छी है लेकिन दु:ख की बात यह है कि जिन पंचायतों से यूनानिमस रैजोल्यू ान आये थे उनको रद्द कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि किन हालात में उन रैजाल्यू ान को रद्द कर दिया गया है और वहां पर दोबारा ठेके नीलाम किये गये है। मैं

चाहूंगा कि जहां की पंचायत भाराब का ठेका नहीं चाहती वहां उस ठेके को बंद कर दिया जाये। इसके बाद मैं डिमांड नं 20 पर यह कहूंगा कि यह ठीक है कि हरियाणा में सड़कों की बढ़ौतरी हो रही है लेकिन मेरे हल्के में सात गांव जमना के बांध और वाटर स्ट्रीम के बीच है। इनमें बहुत बर्बादी हुई है। ये गांव है कामलपुर, हलवाना, नबियाबाद, नंगल, गुडियाना, जपती छपरा और बदीद छपरा। इन गांवों में लोगों के घर और फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई है और वहां पर कोई भी सड़क नहीं है। मैं चाहूंगा कि फ्लड कंट्रोल के लिये जो पैसा रखा गया है उसमें से पैसा निकाल कर इन गांवों में सड़के बनाई जाये। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा हल्का फ्लड इफैक्टिड एरिया है इसलिये वहां पर खास ध्यान दिया जायें और जहां के लिये मैंने सड़के बनाने के लिये अर्ज की है वहां पर सड़कें जरूर बनाई जाये। इसके बाद मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कंचोड़ के नजदीक दरिया जमुना पर एक पुल जरूर बनाया जाये। अगर वह पुल बनाया जाता है तो उससे यातायात बढ़ेगी और सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे हल्कें में 70 प्रति ात सड़कें ऐसी है जिनके दोनों ओर दरखत नहीं है इसलिये उनके दीनों किनारों पर दरखत लगवाये जाएं इसके अलावा दरिया जमना के पास भी फ्लड प्रोटैक ान के लिय दरखत लगाये जाये। इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

चौधरी भाकरूल्ला(फिरोजपुर झिरका): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं डिमांड नं0 8 पर बोलना चाहूंगा। आपको मालूम है कि मेरा मेवात का इलाका है जोकि बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है। मैंने मुख्य मंत्री जी से भी इस बारे में बात की थी, उन्होंने मेरे से लिस्ट मांगी थी और मैंने उन गांवों की लिस्ट उन्हें दे रखी थी जहां पर सड़कों की बहुत जरूरत है। लेकिन इसके अलावा मेरे गांव की एक बहुत जरूरी मांग है। मैं इस मांग को उस समय से मांगता आ रहा हूं जब से मैं एम0एल0ए0 बना हूं। इस बारे में मैं लिख कर भी दे चुका हूं और कई बार मुख्य मंत्री जी से खुद भी मिल चुका हूं। मेरे गांव में एक घाटी है वहां पर सड़क का काम भ्रारू हुआ.....

श्री उपाध्यक्ष: आप यह लिस्ट मिनिस्टर साहब को दे दें, वे इस पर विचार कर लेंगे। आपका समय भी हो गया है।

चौधरी भाकरूल्ला: मैं एक बात कह कर बैठता हूं? वहां पर एक एस0डी0ओ0 अरोड़ा बैठा हुआ है और उसने वहां पर एक मेट भी लगा रखा है। अभी 13.1.79 की बात है कि वहां पर जो मजदूर काम करते है उनके हर एक के 164 रूपये बनते थे लेकिन उनको दिये गये 116 रूपये के हिसाब से। फिर उनको धमकी दी गई कि अगर इस बारे में किसी से बात की तो अच्छा नहीं होगा। बाद में जब फिर लेबर लगाई गई तो उनको पैसें नहीं दिये गये। मैं यह सारे मामलें की कापी मिनिस्टर साहब को

दे दूंगा और मैं आपके द्वारा मंत्री जी से गुजारि ा करूंगा कि घाटी पर जो मजदूर काम कर रहे है उनको पूरे पैसे दिये जाएं। इसके अलावा मेरी मंत्री साहेबान से मांग है कि मेरे गांव तिगांव से रेजोल्यू ान भी आया था कि वहां पर करीब दो किलोमीटर लम्बी सड़क की जरूरत है। मेहरबानी करके उसको बनाया जाये।

स्वामी आदित्यवे ा(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 24 तथा 25 का टोटल 224 करोड़ है। मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सारे बजट को पढ़ने से लगता है कि इसमें ज्यादा खर्च अन्य खर्चों पर तथा कार्यलयों पर किया गया है। इस बजट में पांच करोड़ रूपया अन्य खर्चे का है जिसका हिसाब मैं आपको बताना चाहता हूं। मांग नं0 7 में 27 लाख रूपया है जिसमें से दो लाख रूपया तो कर्मचारियों के वेतन आदि का खर्चा है और बीस लाख रूपया अल्प बचत के लिए पुरस्कार देने के लिए रखा गया है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने मेहनत करके खून–पसीने की कमाई बचाई है उनके लिए कोई पुरस्कार की बात नहीं रखी है। इसी प्रकार से लोक निर्माण विभाग के तमाम कार्यालयों का खर्चा 8 लाख 62 हजार रूपया है इसके अतिरिक्त कई लाख रूपये अन्य खर्चा है तो अगर इस सारे बजट में से पांच प्रति ात की कटौती की जाये तो बसों का जो किराया बढ़ाया गया है उसको बढ़ाने की कोई आव यकता नहीं पड़ेगी। हरियाणार में बसों के किराये बढ़ाना गरीबों के साथ ज्यादती करना है। वित मंत्री जी तो बड़े

समाजवादी है, गरीबों की हिमायत करने वाले है मैं उम्मीद करूंगा कि वे आज सदन के समानै घोशणा जरूर करेंगे कि अन्य खर्च और कार्यालय के खर्च में कटौती करके बसों के किरायें में एडजस्ट करेगे क्योंकि यह किराया हरियाणा के लोगों पर ज्यादती है। इसी प्रकार मांग संख्या 24 पर्यटन यानी टूरिजम की है। इसमें कुल 34 लाख रूपये है। 34 लाख में से 15 लाख रूपये मैनटनैंस यानी सधारण पर खर्च होने है। यह संधारण क्या बला है, इसकी पूरी व्याख्या नहीं की गई है? जबकि पर्यटन सारे हरियाणा के लिए सफेद हाथी है इससे हरियाणा को एक लाख की आमदनी होती है ओर इस पर 34 लाख रूपये खर्च कर रहे है और इसमें से मैनटेनैंस पर 15 लाख खर्च होंगे। यह तो हरियाणा पर बोझ ही है। जो जनता की खून पसीने की कमाई है उसका ठीक प्रयोग नहीं हो रहा है। यह सुझाव मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए दे रहा हूं।

आवाजें: आप जनता पार्टी को छोड़ क्यों नहीं देते?

स्पामी आदित्यवे I: अभी तो जनता पार्टी ठीक चल रही है जब ठीक नहीं चलेगी तो आप को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं क्या बात है, जब मैं खड़ा होता हूं तो इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है। इसी बात पर मुझे एक उर्दू का भोयर याद आ गया। किसी ने कहा है कि–

जब हम आहें भी करते है तो होते है बदनाम।

वो कतल भी करते है तो चर्चा नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा भूमि देव भूमि है, ऋशियों की भूमि है। संस्कृत में एक भलोक है–

यावत् जठ्रे ही प्रियते तावत् स्वतं ही देहिनाम्।

अधिकं यो अभिमन्येत् सस्तेनी दण्डम् अहर्ति।।

भूख भाांत करने के लिए जितने अन्न की जरूरत है उतने पर ही प्रत्येक प्राणी का अधिकार है उससे अधिक जो आ ाा रखता है वह चोर है और दंड का भागी है। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्शित करना चाहता हूं कि अन्य खर्च और कार्यलय के खर्च में से कटौती करके गरीब किसान–मजदूर पर जो कर लगाए गए है उनको कम किया जाये। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कृशि मंत्री(ब्रिगेडियर रण सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत अपने भाईयों को दो चार जरूरी बातैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो फि ारीज डिपार्टमैंट है इस के अन्दर आपको जानकर यह खु ाी होगी कि इसी साल हमारी आमदन और पैदावार दोगुनी हो जायेगी। कहां तक हुड्डा का तालुक है वह हम हरियाणा के अन्दर कलोनीज बनाते ही हैं इसमें भी आप देखेंगे कि पिछले 3–4 महीनों से बिल्डिंग एक्टीविटी की रफतार काफी बढ़ी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो कालोनी पंचकूला में बन रही है वह चंडीगढ़ से बढ़कर नहीं होगी

तो बराबर तो हेागी ही। जसे सबसे बड़ी बात है मैं मैम्बर साहेबान का ध्यान उस ओर भी दिलाना चाहता हूं वह है कौप इं योरैंस, फसल का बीमा। इसके बारे में हम सब बहुत दिनों से बलिक पचासों सालों से भाोर मचा रहे है, आ वासन भी दे रहे है और भी सोचा है लेकिन इस बारे में सारे हिन्दुस्तान के अन्दर कोई काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं अगर इस काम को हम सब मिलकर करें तो किसान का हमे ाा के लिए कल्याण हो जायेगा। इसलिए मैं अपने साथ्यिों के सामने कुछ सुझाव रखूंगा जिसके बारे में हमें गौर करना चाहिए और जल्दी ही इसके लिए ऐसे कदम उठायें ताकि इस भाुभ काम को जल्दी पूरा कर सकें। अब आप देखिए कौन सी सरकार ऐसा काम कर रही है? मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए काफी कर रही है। इतना कर रही है कि हमने सारे हिन्दुस्तान में एक मिसाल कायम कर दी है। जैसे अभी ओलों की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमने तीन सौ रू0 फी एकड़ दिया जहां पचास प्रति ात से ऊपर नुक्सान हुआ। आज तक हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस साल इससे हमारे ऊपर तकरीबयन 10–12 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हर साल इन चीजों पर 10–12 करोड़ रू0 खर्च करती हो। आप हमारी डिवैल्पमैंट एक्टीविटीज भी देख रहे है जैस सड़कें है, नहरें है, हस्पताल है, तो अगर ऐसे ही कुदरत का प्रकोप रहा तो इन पर हमें कम खर्च करना पड़ेगा जिससे हमारे डिवैल्पमैंट के कामों

में रूकावट आएगी जाकि हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आप सब भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि यह बहुत अहम मसला है। हमें कोई ऐसी जतवीज सेाचनी चाहिए जिससे कि हमें हर साल आठ करोड़ या दस करोड़ रूपया ब्याज के रूप मिल जाये तो जो नैचुरल क्लायमिटिज की वजह से ऐसी आफत आती है, खासतौर से ओले याह हेल स्ट्रोम से। इससे किसानों को बचाने के लिए मदद मिल सकेगी। इसीलिए 3–4 बातें मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं अगर कोई फण्ड 60 करोड़, 80 करोड़ या 100 करोड़ रूपये का इक्ट्ठा हो जाए तो कहना ही क्या है? अगर ऐसा हो जाए तो उससे 8–10 करोड़ रूपये ब्याज मिल सकता है जिससे हम किसानों की मदद कर सकते है। इस काम के लिए सरकार भी एक दफा बीस करोड़ दे सकती है। इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड है वह भी मदद कर सकता है। कोआप्रेटिव बैंक हैं वे भी मदद दे सकते है। क्योंकि यह पायलट प्रोजैक्ट होगा इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी इसमें मदद देगी। चूंकि हम किसानों के लिए इतना बड़ा भारी काम करने जा रहे है इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि वे इससे खु ा ही होंगे, उनको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। इस फंड के लिए किसानों से फी एकड़ दो रूपये, तीन रूपये और चार रूपये जा भी ठीक समझते है उसके बारे में सोचना पड़ेगा और फैसला लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी फैसला करेंगे उतना अच्छा है। आप यह देखें कि आम तौर पर रबी की फसल के समय फरवरी, मार्च में ओले पड़ते है। बहुत से

गांवों में इस साल भी बहुत ओलें पड़े हैं। जैसे बहादुरगढ़, करनाल और कुरूक्षेत्र इलाकों में और भी जगह ऐसी है जहां पर ओलों की वजह से किसान बिल्कुल बर्बाद हो गए है। उनकी फसल का एक दाना भी नहीं बचा। अफ्सोस की बात तो यह है कि रबी की फसल के समय यह ओले आ जाते है, दूसरी फसल तो बाजरा और ज्वार ही रह जाती है जो कि सिर्फ चारे की फसल है। इसलिए जब किसानों की रबी की फसल में ओले आ जाते है तो किसान बहुत दुखी हो जाता है और एक तरह से वह खत्म ही हो जाता हैं दूसरी बात हमैं सोचनी पड़ेगी कि आया हम सब चीजों का बीमा करें या सिर्फ ओलों का ही बीमा करें। सब चीजों का अगर हम बीमा करें तो किसानों को प्रिमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा प्रांत में सिर्फ ओलों की वजह से ही नब्बे फीसदी नुकसान होता है। तो मैं यह समझता हूं कि यह भी सारे सदन के लिए काबिले गौर बात होगी कि at the beginning we may only start with insurance against hailstorm. दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं जैसे कि मेरे बहुत से भाईयों ने कहा है कि अच्छा तो यह होगा की सारी स्टेट में इसको कम्पलसरी लागू किया जाए। लेकिन प्रजातंत्र राज में अच्छा यही है कि हम इसके बारे में जनता के विचारों की भी जांच–पड़ताल करें। मैं आज इसलिए खड़ा हुआ हूं कि हर एक साथी मेरी इस बात पर गौर करके अपने हल्के के लोगों से बातचीत करे और जो उनके विचार या सुझाव है। वह हमें दें। इन सब चीजों की

जांच पड़ताल करके हम एक मीटिंग बुला लेंगे ताकि उसमें इस चीज को पूरा करने के लिए आगे कदम उठाएंगे।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि भाव का भी ख्याल रखें। आज गुड़ का भाव 25 रूपये मन से ज्यादा नहीं है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(श्री बीरेंद्र सिंह): यह हमारी पालिसी नहीं है, यह तो सैंट्रल गवर्नमैंट की पालिसी है।

ब्रिगेडियर रण सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने एक दिन एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमने एक साल के अन्दर–अन्दर चने का भाव कहां से कहां कर दिया।

श्री प्रीत सिंह: अच्छा जी। जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने जो चौपालों का प्रोग्राम दिया है, इसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस चौपाल के निर्माण के लिए फाउंडे ान स्टोन रखा जा चुका है, वह जरूर बनेगी और उन चौपालों पर काम जारी है। अभी एक और स्कीम चालू की है, 25 तारीख को उसको उद्घाटन किया है। वह स्कीम है हरिजनों के लिए होस्टल बनाने की। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आज हरिजन वर्ग को सबसे ज्यादा जरूरत ि ाक्षा की है। बगैर ि ाक्षा के, सोशल, इकोनोमिकल और पोलिटीकल इक्वैलिटी नहीं आ सकती। इस चीज का ध्यान रखते हुए सरकार इनकी एजुके ान पर ज्यादा ध्यान दे रही है

और इनकी भलाई के लिए बहुत सी स्कीमें तैयार कर रही है ताकि छोटे बच्चे की ि ाक्षा से ले कर हायर स्टडी तक के बच्चों को ग्रांट, एड या दूसरी किस्म की सहायता दी जा सके। डिप्टी स्पीकर साहब, हम ने प्रिपरेटरी स्कूल खोलें है ताकि मैट्रिक पास हरिजन जो कम्पीटीजिटव एग्जाम में बैठते है और पास भी हो सकसते है, उनको फ्री ट्रेनिंग दें। रोहतक, भिवानी और अम्बाला में इस प्रकार के तीन सैंटर काम कर रहे है। कई सदस्य होस्टल के बारे में जिक्र कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट करनाल के अन्दर, टैंटेटिव बेसिज पर होस्टल खोलें है और अगर उन बच्चों को ि ाक्षा दी जाएगी जिनके पेरैंटस को समाज में घृणा की दृश्टि से देखा जाता है। घृणा का मतलब है अगर वह हरिजन क्लास से ताल्लुक रखता है और सफाई का काम करता है या इस किस्म का प्रोफै ान करता है जिसे से समाज नफरत करता है, ऐसे पेरैंटस के बच्चों को इन होस्टल्ज में एडमिट किया जाएगा और प्रति बच्चे पर 145 रूपये खर्च होंगे। आप इस से अन्दाजा लगा सकते है कि सरकार हरिजनों की बहबूदी के लिए कितनी लगन से कार्य कर रही है। धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री(श्री लछमन सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो रोड्ज के मुताल्लिक मेरे किसी साथी ने कोई खास बात नहीं कही। इससे साफ जाहिर होता है कि जितने मैम्बर हाउस में मौजूद है, सब रोड्ज कसे काम की तारीफ करते है।

श्री दीप चंद भाटियाः डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। हमें तो बोलने के लिए टाईम दिया ही नहीं गया। लेकिन फिर भी मैं हाउसे को बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में एक किलामीटर सड़क भी नहीं बनी। इसलिए यह कहना कि सभी खु ा है, गलत है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन खु ा है। या तो ये खुद ही खु ा है या एक आधे और खु ा होगा। (व्यवधान)

श्री लछमन सिंहः मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं कि 1975–76 में कांग्रेस सरकार ने रोड्ज पर 3 करोड़ 95 लाख और 1976–77 मैं 4 करोड़ 90 लाख खर्च किया था। मेरे भाई पोहलू साहब ने बजट में 38 करोड़ को प्रोवीजन पढ़ कर एकदम कह दिया कि 19 करोड़ रूपये की बेइमानी कर गये। मैं पोहलू साहब को बताना चाहता हूं कि जब 38 करोड़ में से हमने इस साल 11.43 करोड़ रोड्ज पर खर्च करना है तो इस में 19 करोड़ का घपला कैसे हो सकता है। यह वेग एलगे ान है, इस तरह का एलीगे ान लहीं लगाना चाहिए। पोहलू साहब मेरे साथ वजीर रह चुके है। हम इनको छोटा वजीर के नाम से पुकारा करते थे उसके बाद ये एक बार भी वजीर नहीं रहे, हां जेल में जरूर रहे। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, पी0डब्ल्यू0डी0 के अफसरों की नालेज, उनकी काबलियत का अन्दाजा, हाउस इस बात से लगा सकता है कि गवर्नमैंट आफ इंडिया के प्लानिंग ग्रुप ने जितना पैसा पंजाब को दिया, उतना ही हरियाणा को सैंक ान किया।

अगली प्लान में 85 करोड़ रूपया दिया है, पंजाब हम से एक पैसा भी फालतू नहीं ले सका, हालांकि उसका रकबा हरियाणा की निस्बत बड़ा है। इसलिए आपका जो एलीगे ान है वह निराधार है। डिप्टी स्पीकर साहब, हाउस की कार्यवाही को चलते हुए एक महीना गुजर चुका है। हर महकमें के खिलाफ कोई न कोई ि ाकायत आई है, लेकिन पी.डब्ल्यू.डी. ही एक ऐसा महकमा है जिस के खिलाफ किसी मैंबर ने ि ाकायत नहीं की है। श्री भाकरूल्ला साहब ने थोड़ी सी ि ाकायत की थी, मैंने उनको कहा था कि लिख कर दें।

स्वामी आदित्यवे ाः हमारी सरदार जी किस खु ाफहमी में रहते है। सब से ज्यादा विवाद सड़कों पर रहता है और यह सब मैम्बर जानते है। (व्यवधान)

चौधरी बीरेंद्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मंत्री महोदय ने कहा कि इन के महकमें के बारे में कोई ि ाकायत नहीं आई, यह गलत बात है, दरअसल हम सारी ि ाकायतें इनके कमरें में ही करके आये है। (हंसी)

श्री लछमन सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, अपोजी ान के दोस्त जिस लहजें से बात कर रहे है इससे यह अन्दाजा लग सकता है कि जो ये नुक्ताचीनी करते है वह बिल्कुल गलत है और उसमें कोई जान नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पोहलू साहब को बताना चाहता हूं कि हम 2800 किलोमीटर रोड्ज यानी 1800र

किलोमीटर सिंगल लिंक्स और एक हजार किलोमीटर के करीब मिसिंग लिंकस सन् 1982 तक पुख्ता बनाएंगे (विघ्न)। डिप्टी स्पीकर साहब, यह 2800 किलोमीटर सड़कें बनाने का हमार बहुत बड़ा ऐमबि ियस प्रोग्राम है। हम इसको जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाना चाहते है। (विघ्न) इसी तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अ योरैंस दी है उसके अनुसार सारी स्टेट में जितने भी सिंगल लिंकस है उनकों अगले तीन सालों में पक्की सड़कौं से जोड़ दिया जाएगा। हमारे पास पैसे है और प्लान के अन्दर इसके लिए प्रोविजन है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों इस बात का भाक रहता है। स्वामी आदित्यवे ा जी को तो हर चीज पर भाक रहता है। यहां तक कि इनको अपने आप पर भी भाक रहता है। पता नहीं इनको पास क्या चीज है जो यह मेरे कमरे में आने से भी डरते है। इनको अपने आप पर पूरा कांफिडैंस होना चाहिए।

स्वामी आदित्यवे ाः डिप्टी स्पीकर साहब, इनके कमरे में मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहां ये हर चीज का मजाक उड़ा देते है (विघ्न)

चौधरी संत कंवरः डिप्टी स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर।.....

Mr. Deputy Speaker: This is no point of order. It should be expunged.

स्वामी आदित्यवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, इनसे कहा जाए कि इस तरह के झूठे व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: वह मैंने कह दिया है। (ाोर)

श्री लछमन सिंह: तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पोहलू साहब को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि आप कांग्रेस (आई) में जाकर के नए नए मौलवी बने है परन्तु आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ साल पहले आप मेरे साथ भी बैठा करते थे। (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे से पहले सरदार लछमन सिंह जी चूंकि 15 साल तक कांग्रेस मैं रह चुके है इसलिये ये पुराने मौलवी है। (हंसी)

श्री लछमन सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, पिछली पांच साल योजना में कांग्रेस सरकार ने 22 करोड़ रूपया सड़कों के लिये मंजूर कराया था लेकिन इस दफा चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने छठी पंचवर्शीय योजना में 85 करोड़ रूपया लिया है। अब आप देखें कि कितना ज्यादा रोड्ज का काम होने वाला है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि पोहलू साहब का जो ऐलीगे ान है यह बिल्कुल वेग है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एकाध कोई एस0डी0ओ0 होगा, जिसको ये डराना चाहते है। ये उसे दिखाना चाहते थे कि मैंने असैम्बली में भी यह बात कह दी है। (विघ्न) अब ये उसे कहेंगे कि रात को मुझे मिल लेना वरना मैं तुम्हारी

ि ाकायत कर दूंगा। (विघ्न) इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए अपना स्थान लेता हूं।

आबकारी तथा कराधान मंत्री(चौधरी भोर सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मांग नं0 5 पर, जो आबकारी एवं कराधान विभाग से संबंधित है, कई विधायकों ने अपने विचार रखे। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने बोलते हुए कहा कि ठेकेदार को भाराब की बोतल 26 रूपये घर में पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब लाटरी सिस्टम चालू किया था तब भी इन को एतराज था और अब जब ओपन आक ान में दुकानें दी गई तब इनको एतराज है। बोतल 26 रूपये में बिके या 27 रूपये में बिके, पीने वाले उसे अपने हिसाब से लेंगे। इनका कहना यह भी था कि जब ठेकेदार को 26 रूपये में बोतल पड़ेगी तो वह 18 रूपये में कैसे बेचेगा? इसके बारे में अर्ज यह है कि हमने कोइ कीमत निर्धारित नहीं की है कि वह 18 रूपये में ही बेचेगा। वह उसे चाहे 26 में बेचे, 27 में बेचे या 28 में बेचे यह उसकी मर्जी है। फिर उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा कि भाराब के जो ठेकेदार है उनके ऊपर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती चाहे उनकी भट्ठी ही क्यों ने पकड़ी जाती है तो उसमें पुलिस की कार्यवाही होती है लेकिन अगर उनका मतलब यह हो कि भाराब के ठेके से बोतल से जो सैम्पल लिया जाता है उसको भी पुलिस में भेजा जाए तो वह नामुमकिन सी बात है। उसके ऊपर तो हम विभाग में ही कार्यवाही करते है

क्योंकि उसमें ज्यादा सहूलियत है। ऐसे केसिज में हमने चार लाख रूपये पैनल्टी के रूप मैं प्राप्त किए है। (विघ्न)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब इतनी बड़ी मिलावट करने वालों को पैनल्टी लगा कर छोड़ दिया जाता है तो क्या आम जनता के जो लोग भाराब निकालते पकड़े जाते है उनको भी पैनल्टी लगाकर छोड़ दिया जाएगा?

चौधरी बीरेंद्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने यह नहीं कहा था कि हर दुकान पर 26 रूपये की बोतल बिकगी। किसी दुकान पर यह 30 रूपये की भी बिक सकती है। मैंने तो एक ठेके की मिसाल दी थी।

चौधरी भोर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, भाराब अगर सस्ती बिके तो राव साहब एतराज करते है और अगर मंहगी बिके तो चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ऐतराज करते है। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने यह भी कहा कि असैसिंग अथोरिटी और पार्टी अगर आपस में मिल जाए तो सरकार अपील में नहीं जा सकती। इसमें पोजी ान यह है कि हर असैंसिंग अथेरिटी के काम की हमारे अपने लैवल पर भी इंस्पैक ान होती है और उसके साथ ही साथ ए0 जी0 आफिस से जो आडिट पार्टी जाती है वह भी कई केसिज में सैंट परसैंट निरीक्षण करती है। उनके द्वारा, एक्साइज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट के नोटिस में जो

बातें लाई जाती है उनके बारे में ऐक्साइज एंड टैक्से ान कमि नर को यह अधिकर है कि वह ऐसे केस को उससे हायर अथोरिटी को सुओ मोटो ऐक ान के लिए भेज दें। हर महीने और हर साल ऐसे केस होते है इसलिए अपील में जाने की जरूरत नहीं है।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हर साल बहुत से केस होते है लेकिन मैं आपकों बताऊं कि डिपाटमैंट की सुओ मोटो केसिज की परसैंटेज .1 है। अगर ये चाहें तो मैं इनको फिगर्ज सप्लाई कर सकता हूं।

चौधरी भोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पता है कि इनके पास फिगर्ज है और वे फिगर्ज इन्होंने ऐस्टीमेटस कमेटी को सप्लाई किए गए मैटीरियल से ली होगी लेकिन मैं इनकों बताना चाहता हूं कि जो भी केस असैसिंग अथोरिटी के खिलाफ हमारा आडिट सैल या ए0 जी0 साहब की पार्टी हमारे नोटिस में लाती है उस पर सुओ मोटों ऐक ान लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, विज साहब ने कहा कि बैरीयर्ज के ऊपर जो गड़बड़ हेाती है उसको मैं उनके साथ ट्रक में चल कर देखूं। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज यह है कि बैरीयर्ज लगाए ही इसलिए गए है कि बाहर से जो माल आता है उसकी वे पड़ताल करके भेजें। कई बार अनलोडिंग भी करानी पड़ती है। मैंने बहुत से बैरीयर्ज चैक भी किए है और मैं इनके साथ ट्रक में

जाने के लिए भी तैयार हूं। मैटाडोर का जहां तक संबंध है, उनमें हम पंद्रह सौ रूपया टैक्स लेते है। अगर वे औवर लोडिंग करके चलते है तो इस बात को देखना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट का काम है, ऐक्साईज एंड टैक्से ान डिपार्टमैंट का नहीं। (विघ्न)

मूलचंद मंगला जी ने सेल्ज टैक्स के बारे में कहा था। कई फार्मों का जिक्र उन्होंने किया। इसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनी हुई है। वह जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगी।

फिर उपाध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि हलवाई चूंकि अनपढ़ है इसलिए उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम इसकी स्टेजिज बनाने के लिए तैयार है। सैक्ान 26 के तहत एक स्टेज दो स्टेज या तीन स्टेज पर एक ही बार यह टैक्स ले लिया जाया करेगा।

वित मंत्री(श्री मूल चंद जैन): डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नम्बर चार और पांच पर तो दूसरे मिनिस्टर साहब भी कुछ जवाब दे चुके है। डिमांड नम्बर सात जो अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज के बारे में है, उस पर अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक डिमांड नम्बर 25 का सवाल है वह लोन एंड एडवांसिज के बारे में है और इस पर कोई खास एतराजात नहीं हुए है। मैं एक–एक दो–दो मिनट हर डिमांड पर लेना चाहता हूं। डिमांड नम्बर चार का जवाब दिया जा चुका है। डिमांड नम्बर पांच के बारे में भी

थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पहले डिमांड नम्बर एक के बारे में अर्ज करना चाहता हूं जो विधान सभा के बारे में है। विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं जो विधान सभा के बारे में है। विधान सभा के कर्मचारियों के बारे में बहिन सुशमा जी ने और एक और सदस्य ने ध्यान दिलाया है। उन कर्मचारियों के वेतन ग्रेडज तथा स्टाफ की कमी के बारे में कहा गया है और यह भी कहा गया है कि ज्यादा पौस्टस कियेट होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे विधान सभा की तरफ से सुझाव आयेंगे उन पर सरकार तथा फाइनैंस डिपार्टमैंट हमदर्दाना तौर पर विचार करेगा। (तालियां)

डिप्टी स्पीकर साहब, डिमांड नंबर पांच पर हमारे साथियों ने कुछ जिक्र किया है उनका जवाब तो मिनिस्टर साहब ने दे दिया है लेकिन फिर भी मैं हाउस का ध्यान एक दो बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। बहिन सुशमा जी ने कहा है कि क्वांटम बढ़ाने से भी ट्रेडर्ज को बिक्री टैक्स देना पड़ता है। अब जिस व्यापारी की चालीस हजार तक की सेल होगी उसको लाइसैंस नहीं लेना पड़ेगा। अब चालीस हजार से एक लाख तक सेल करने वाले को लाइसैंस लेना पड़ेगा। जो मैनुफैक्चरर है उनके क्वांटम की मिकदार 10 हजार से 25 हजार कर दी है। जो दलील बहिन सुशमा जी ने दी है वह ठीक है कि जिनकी मात्रा पहले कम थी यानी जो लाइसैंस नहीं लेते थे उनको बड़े लाइसैंस

वालों से बिक्री टैक्स देकर माल खरीदना पड़ता था। अब इससे कुछ लाइसैंस फीस का नुक्सान होगा। यह बात भी ठीक है कि बिक्री टैक्स में फर्क नहीं पड़ना चाहिएं।

डिमांड नम्बर सात और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज के बारे में है। उसमें हरियाणा भवन के बारे में भी यहां जिक्र आया। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी इस सिलसिले में जिक्र किया। मुझे खु ाी है कि उन्होंने यहां हाउस में जिक्र किया लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सरकार को जब इस बात का पता चला कि हरियाणा भवन में और दूसरे रैस्ट हाउसिज में चाहे वे जिला स्तर पर है सब में घाटा पड़ रहा है तो हमारी सरकार ने उसी वक्त उस पर विचार किया। चाहे कोई नहर का रैस्ट हाउस है, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. का है चाहे किसी कारपोरे ान का है हरेक घाटे में चल रहा है। यह बहुत पुराने जमाने से रीति चली आ रही है। मुझे तो इस बात पर भी ताज्जुब हुआ कि कांग्रेस के जमाने से कई रैस्ट हाउसों में चीफ मिनिसटर साहब के लिए और गवर्नर साहब के लिए कमरे हर समय रिजर्व रखे जाते थे। उन कमरों की किसी के लिए भी बुकिंग नहीं हो सकती थी। मिसाल के तौर पर हरियाणा भवन में नीचें के काफी कमरे और हाल गवर्नर साहब के लिए रिजर्व होते थे। उनको कोई अफसर नहीं ले सकता था और न कोई मिनिस्टर ले सकता था चाहे गवर्नर जाये या न जायें। वे खाली पड़े रहते थे।

इसी तरह से दूसरी मंजिल के कुछ कमरे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए रिजर्व किये हुए थे। दूसरों को ठहरने की कोई इजाजत नहीं थी। यह बात कांग्रेस के जमाने से चलती आ रही थी। यह बात न सिर्फ हरियाणा भवन में ही थी, बल्कि इस किस्म का प्रोविजन दूसरे भवनों में भी था। मुझे खु ाी है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है इस किसम की रिजर्वे ान है तो वह नहीं होगी। आइन्दा हमे ाा के लिए न चीफ मिनिस्टर साहब के लिए और न ही गवर्नर साहब के लिए वे कमरे रिजर्व होगें।

चौधरी बीरेंद्र सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। फाइनैंस मिनिस्टर साहब को इस बात का पता नहीं है कि हरियाणा भवन में दो कमरे हर वक्त चीफ मिनिस्टर स्टाफ के लिए रिजर्व रहते है जो आम आदमी को या एम0एल0ए0 को नहीं दिये जाते है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। फाइनैंस मिनिस्टर साहब कांग्रेस की बात क्यों कर रहे है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से एम0पी0 रह चुके हैं?

श्री मूल चंद जैनः जब सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब के लिए रिजर्वे ासन कराई जायेगी तो वे कमरे रिजर्व होंगे वरना वे हमे ाा के लिए रिजर्व नहीं होंगे चाहे वे कमरे किसी भी रैस्ट हाउस में होगं। परमानैंट तौर पर चीफ

मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब के लिए रिजर्व नहीं होंगे दूसरे मंत्री जायेंगे तो उनके लिये होंगे। जैस पहले होता था कि वे परमानैंट तौर पर खाली रहते थे ऐसे नहीं रहेंगे। पहले तो ऐसा होता था कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब दो–दो चार–चार दिन उन रैस्ट हाउसिज में जाते थे या साल में एक महीने भर के लिए जाते थे तो बाकी 11 महीने तक वे कमरे खाली ही पड़े रहते थे, बिल्कुल नहीं बरते जाते थे। यह एक प्रकार से फिजूलखर्ची थी। मुझे अफसोस है कि यह प्रथा कांग्रेस के जमाने से चली आ रही थी। आज जब हम विजिलैंट हुए तो पता चला कि यह मसला है। अपोजि ान के भाई और ट्रैजरी बंचिज के भाई जितने भी विजिलैंट होंगे तो उतने ही हमारे कर्मचारी भी विजिलैंट होंगे और केबेनिट भी विजिलैंट होगी। मैं भी फर्ज से पीछे नहीं हट रहा हूं, मुझे भी विजिलैंट रहना चाहिए लेकिन उनको भी अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। उनको बजट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए था लेकिन जैसे अभी कार्यालय की बात कही कि कार्यालय में क्या होना चाहिए, ये तो वेग किस्म के आरोप है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि अपोजि ान के साथी और ट्रेजरी बेंचिज के साथी बजट के चारों डाकूमैंटस को पढ़ें यानी जा चार बड़ी–बड़ी किताबें है उनको पढ़ना चाहिए मुझे भी इस बात पर अफसोस है और भार्म भी महसूस करता हूं कि मैं भी इन चारों डाकूमैंटस को नहीं पढ़ पाया हूं। फाइनैंस मिनिस्टर होने के नाते मुझे मालूम होना चाहिए लेकिन इनमें इतने सारे आंकड़े है जिनका मुझे भी पता नहीं। इतने डाकूमैंटस को पढ़ना

तो बड़ा कठिन होता है लेकिन मुखतलिफ सबजैक्ट को अलग अलग एम0एल0ए0 समझने की कोि ा ा करें। एक के लिए पूरा समझना तो मु कल हो जायेगा लेकिन वे अलग–अलग महकमें छांट लें, उन का अध्ययन करें और कंस्ट्रक्टिव सुजैक ान दें। अगर कोइ कंस्ट्रक्टिव सुजै ान आती है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तुरन्त प्रतिकिया होती है। अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा भवन का इ ारा हुआ। उन्होंने पूछा कि यह मामला क्या है? क्या किटिसिज्म ठीक है कि हरियाणा भवन में पांच छः लाख रूपये नुकसान होता है और वह हरियाणा सरकार को सबसिडाइज करना पड़ता है। वहां पर सरकारी कर्मचारी, चीफ मिनिस्टर साहब और एम0एल0एज0 साहेबान भी कभी–कभी ठहरते है। हरियाणा भवन में छः लाख रूपए का घाटा होता है और उस को पूरा करने के लिए हम जनता पर टैक्स लगायें, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अपर तबकें को ठहरने के लिए सबसिडाइज करें तो गलत बात है। मुझे बड़ी खु ी है कि सी.एम. साहिब के मि वरे से मैं यह घोशणा करना चाहता हूं कि हरियाणा भवन की जो कैंटीन है, उसमे जो खाना–पीना है वह अब नो प्रोफिट नो लौस बेसिज पर चलाया जायेगा। केवल यही नहीं बलिक जहां भी सरकार की तरफ से कैंटीनें चलती है चाहे वे रोडवेज की है या और उनको इसी बेसिज पर चलाया जायेगा। इसके अलावा हरियाणा भवन में जो कमरे है उनका किराया भी कम है इसलिए यह निर्णय लिया गया है और चीफ मिनिस्टर साहब ने आदे ा दिया है कि मैं ऐलान

करूं कि तमाम किराया दोगुना ही जाएगा। पाचं रूपये का दस रूपये होगा।

आवाजें: अफसरों का कितना होगा?

श्री मूल चंद जैन: जितना एम0एल0एज0 साहेबान किराया देते है उतना ही वे देंगे। (विघ्न)

आवाजें: अफसरों का किराया ज्यादा होना चाहिए।

श्री मूल चंद जैन: देखिए, आफिसर्ज के मामले में सदस्यगण को भाायद पता नहीं है। एम0एल0एज0 साहेबान और मिनिस्टर साहेबान को डी0ए0 51 रूपए मिलता है लेकिन सरकारी कर्मचारी जो क्लाव वन है, उनको 23 रूपये मिलता है। (विघ्न)

अगर वे डियूटी पर जायें या और काम से जायें तो वहां पर एम0एल0ए0 साहेबान और अफसरान से दोगुना किराया वसूल किया जायेगा। इसलिये मैंने अब यह घोशणा की है। इसके अलावा मैं अपने ट्रेजरी बेंचिज के भाईयों से भी और अपोजी ान के भाईयों से भी यह प्रार्थना करूंगा कि वे बजट को स्टडी करें।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि यह ठीक है कि अफसर साहेबान तो वहां पर दौरे पर जाते है और उसी हिसाब से वे वहां पर ऐंट्री भी कर

देते है लेकिन एम0एल0एज0 साहेबान का वहां पर दौरे पर जाने का सवाल ही नहीं है। वे तो किसी पोलिटीकल काम की वजह से वहां पर जाते है इसलिये उनको उस दौरान 51 रूपये रोज के मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री देवेंद्र भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब मैं मूल चंद जैन जी की इंटैगरिटी पर डाउट नहीं करता कि एम0एल0एज0 को बदनाम करना चाहते है। लेकिन हमारे एम0एल0एज चाहे वे अपोजी ान वाले है या ट्रेजरी बेंचिज पर बैठने वाले है उनकों अखबार वालों ने तथा अन्य लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है कि इनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी एम0एल0एज0 की आमदनी 1200 और 1000 रूपये महीना की एवरेज से ज्यादा नहीं है। इसमें से भी आधे से ज्यादा खर्चा तो टैलीफोन का जो बिल आता है, उसमें चला जाता है। इसलिये मेरी गुजारि ा यह है कि हम इनकों इतना ज्यादा बदनाम न करें। यह 51 रूपये वाली बात जो आप कहते है यहां पर जनता बैठी सुन रही है, यह समझते है कि हम इनको लूट कर खा गये।

श्री मूल चंद जैन: एम0एल0एज0 के बारे में दुगना की बात तक आयी जब कुछ साथियों ने यहां पर एतराज उठाया। यह एतराज अपोजी ान की तरफ से भी और हमारे ट्रेजरी बेंचिज की तरफ से भी आया था जैसे मैंने पहले ही कहा है कि

एम0एल0एज0 को उसी वक्त डेल अलाउंस मिलता है जब वह दौरे पर होता है–

श्री देवेंद्र भार्मा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी रिक्वैस्ट यह है कि एम0एल0एज0 को पैसे के हिसाब से इतना बदनाम कर दिया गया है कि मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी आप बे ाक पिछली आमदनी की एवरेज निकाल कर देख लें 1000 और 1200 से ज्यादा नहीं निकलेगी।

श्री मूल चंद जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे है। जहां तक बजट का सवाल है मैंने तो मैम्बर साहेबान से सिर्फ इतनी रिक्वैस्ट की है कि बजट के मामले ं में आप हमें सुझाव बतायें, हम उन पर जहां तक हो सकेगा अमल करेंगे। हरियाणा भवन में जहां तक ठहरने का सवाल है, उसके बारे में स्थिति यह है कि अगर कोइ सरकारी तौर पर एम0एल0ए0 वहां पर जाकर ठहरेगा तो उससे दोगुना किराया वसूल किया जायेगा वरना उससे डेढ़ गुना किराया वसूल किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब मैं गिलोटीन एप्लाई करता हूं और डिमांडज को मतदान के लिये रखता हूं।

प्र न है–

कि 34,74,000 रूपए से अनधिक धन–रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग

संख्या 1–विधान सभा के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के कम मैं जायेगें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि 4,31,98,990 रूपए से अनधिक धन–रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 4–राजस्वा के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के कम में आयेंगे।

कि 2,30,71,560 रूपए से अनधिक धन–रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 5–उत्पाद भाुल्क तथा कर के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के कम में आयेंगे।

कि 5,01,92,085 रूपए से अनधिक धन–रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 6–वित के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के कम में आयेंगे।

कि 3,80,73,430 रूपए से अनधिक धन–रा ि ा राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 7–अन्य प्र ाासनिक सेवाएं के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के कम में आयेंगे।

कि 38,05,94,160 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 8–भवन तथा सड़कें के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कि 1,24,98,310 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 11–नगर विकास के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि 6,29,38,210 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 13–समाज कल्याण तथा पुनर्वास के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 95,02,08,800 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 14–खाद्य एवं सप्लाई के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः प्र न है–

कि 71,54,350 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 19–मछली पालन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 3,98,71,940रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 20–वन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः प्र न हैः

कि 33,22,260 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 24–पर्यटन के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

कि 58,25,00,500 रूपए से अनधिक धन–रा ि । राज्यपाल को उन खर्चों को चुकाने के लिए अनुदान की जाए जो मांग संख्या 25–राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्जों तथा पे ागियां के अधीन व्ययों के बारे में वर्श 1979–80 के भुगतान के क्रम में आयेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री उपाध्यक्षः अब सदन कल प्रातः 9:30 बजे तक के लिए स्थगित किया जात है।

(*12.42 hours)

(The Sabhar then *adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 28th March, 1979)